साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-31 अंक- 04 28 जनवरी - 03 फरवरी 2024 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए
महान गणतंत्र दिवस को सलाम
पृष्ठ 6
गणतंत्र दिवस मुबारक मगर...
पृष्ठ 7

हम्मास-इस्राईल जंग

फिलिस्तीनियों का जज़्बा-ए-ईमान देखकर अमेरिकी महिला ने इस्लाम क़बूल किया

फिलिस्तीनियों को आज इज़रायली बम्बारी के नतीजे में जिन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है उसे सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ईमानी जज़्बा बाक़ी है जिससे प्रभावित होकर लोग इस्लाम क़बूल कर रहे हैं।

इजरायल-फिलिस्तीनी युद्ध में फिलिस्तीनियों के बलिदान, इजरायल की क्रूरता, क्रूर हवाई हमले, हजारों फिलिस्तीनी बच्चों की शहादत और गाजा को छात्रों के ढेर में बदलने के बावजूद, फिलिस्तीनियों के धैर्य ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। वे यह सोचने पर मजबूर हैं कि इतने विनाश और विनाश, अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों की शहादत, पानी, पेट, ईंधन और भोजन से वंचित होने के बावजूद, फिलिस्तीनी अपने खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा है वे धैर्यवान और स्तब्ध बनकर उभर रहे हैं। उनकी वजह से उनके रब से कोई शिकायत नहीं होती। उनके दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के क्या कारण हैं? इस संदर्भ में, लोगों ने कुरान पाक का मुआला करना शुरू कर दिया। ऐसे ही लोगों में शिकागो की रहने वाली 24 साल की मेगन बी राइस भी शामिल हैं। उसे पढ़ाई का बहुत शौक है अब उन्होंने गाजा में मानवीय संकट के बारे में बात करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में, उन्होंने कुछ इस तरह कहाः- मैं फिलिस्तीनियों की आस्था और विश्वास के बारे में बात करना चाहती हूं। उनका विश्वास बहुत मजबूत है और लाखों विनाश, भारी हताहत और वित्तीय नुकसान हुए हैं। वे अपने भगवान धुल-जलाल को धन्यवाद देते हैं। दर्द और पीड़ा के बीच भी। यहां तक घ्कि जब उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी वे जो शब्द कहते हैं, वे अपने भगवान के प्रति तज्ञता के शब्द होते हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि जब इस्लाम की पवित्र पुस्तक का अध्ययन करने की बात आती है तो मेघन थोड़ा आलसी हो सकते हैं , कुरान, इसीलिए उन्होंने वर्ल्डर चेन बुक क्लब का आयोजन किया जहां सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग इसे पढ़ सकते हैं। पवित्र कुरान का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। वैसे भी, यह पवित्र कुरान का एक चमत्कार है कि जो लोग पवित्र कुरान का अध्ययन करते हैं, अल्लाह सर्वशक्तिमान उनके मन और हृदय को विश्वास से प्रबुद्ध कर देता है। इसलिए सिकन ने पवित्र कुरान का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कलिमा शहादत का पाठ करने के बाद उसने दमन इस्लाम में शरण ली। अब वह न केवल हिजाब पहनती है, बल्कि इस्लामी शिक्षाओं का पालन करने की भी पूरी कोशिश करती है। रिपोर्ट में प्रकाशित द गार्जियन और डेली ऑनलाइन ने इसे स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन कई महिलाएं कुरान का अध्ययन करती हैं और इस्लाम स्वीकार करती हैं। इस मामले में राइस अकेली महिला नहीं हैं, बल्कि ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो इजरायल की क्रूरता और फिलिस्तीनियों की शहादत से इतनी आहत हुईं कि उन्होंने कुरान का अध्ययन करना शुरू कर दिया और फिर खुद को इस्लाम में बदल लिया। ये महिलाएं अब नियमित रूप से हिजाब पहनती हैं और दूसरों को बताती हैं कि कैसे इजराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने फिलिस्तीनियों के जीवन में अपनी सारी शक्ति लगा दी है। वैसे तो टिक टॉक को समाज में अश्लील हरकतों की गंदगी फैलाने वाला प्लेटफॉर्म कहा जाता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अल्लाह तआला ने अपने असंख्य बंदों को अविश्वास, शिर्क और गुमराही के दलदल से निकालने और उनके दिलो-दिमाग को बदलने के लिए किया है। विश्वास को। रोशनी से रोशन करने का जरिया बनाया। सिर्फ राइस ने टिक टॉक पर कुरान की तिलावत की उन्होंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन इस्लाम के बारे में पश्चिमी मीडिया द्वारा पैदा की गई गलतफहमियों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए, युवा गैर-मुस्लिम महिलाओं ने टिक टोक पर कुछ मिनटों के लिए पवित्र कुरान का पाठ, कुरान की आयतों का अनुवाद सुना, इसका अध्ययन किया। और तब उनकी समझ में आया कि वास्तव में पश्चिमी मीडिया लगातार इस्लाम और मुसलमानों के बारे में भ्रामक प्रचार और झूठ फैलाने में लगा हुआ था। जैसे ही इन युवा महिलाओं ने कुरान का अध्ययन किया, अल्लाह ने उनके लिए व्यापक सोच और व्यापक लेखनी बनाई, और उन्होंने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस संबंध में हैशटैग कुरान बुक क्लब के जरिए कई वीडियो अपलोड किए गए और इस ऐप पर 1.9 मिलियन व्यूज दर्ज किए गए। हालाँकि कुछ लोग पवित्र कुरान के ऑनलाइन पढ़ाई। कोई सोशल मीडिया पर कुरान की आयतें सुन रहा है तो कुछ ऐसे भी हैं जो काम पर जाते वक्त पवित्र कुरान की तिलावत सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। जिससे उन्हें पता चलता है कि पश्चिमी मीडिया जानबूझकर इस्लाम को बदनाम करने में लगा हुआ था। इन शब्दों का इस्तेमाल द गार्जियन.कॉम की एक रिपोर्ट में किया गया था, जिसका शीर्षक था ष्युवा अमेरिकी मुस्लिम फिलिस्तीनी उभार की ताकत को समझने के लिए कुरान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उन युवा अमेरिकी महिलाओं पर रिपोर्ट की गई थी जो फिलिस्तीनी बन गई हैं। विश्वास की भावना और ताकत से प्रेरित आस्था के कारण, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान के मुफ्त ऑनलाइन संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ अमेरिकी युवा कुरान के लिए भुगतान करने और उसका अध्ययन करने को तैयार हैं। #Book Tok Space पर भी गए। इसी तरह, जहां अधिकांश महिलाएं इकट्ठा होती हैं और किताबों पर टिप्पणी करती हैं, वे कुरान पर भी चर्चा कर रही हैं। जरीना ग्रेवाल, जो वर्तमान में येल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, कुरान के बारे में भी बात कर रही हैं। मजीद और अमेरिकी संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता पर एक किताब पर काम कर रही हैं। कहते हैं कि टिकटॉक पर इस मुद्दे पर नया नहीं है। खासकर 11/8 के बाद, अमेरिका और पश्चिमी समाज। मैंने कुरान खरीदा और अध्ययन किया और कुरान सबसे अच्छा विक्रेता था। जरीना ने कहा कि अंतर यह है कि इस बार लोगों ने अध्ययन नहीं किया 17 अक्टूबर को तमस द्वारा किए गए हमले को समझने के लिए कुरान। बल्कि, वे यह समझने के लिए पवित्र कुरान का अध्ययन करना शुरू करते हैं कि इजरायल के अत्यधिक उत्पीड़न के बावजूद मुस्तैनी फिर से कैसे उठे। उन्होंने फिलिस्तीनियों की मान्यताओं और विश्वास, उनकी अविश्वसनीय उच्च आत्माओं और महत्वाकांक्षाओं और नैतिकता और चरित्र को समझने के लिए कुरान का अध्ययन करना शुरू कर दिया है।

फ्लोरिडा के लुंबा की रहने वाली 35 वर्षीय नेटाटर्स मून ने फिलिस्तीनियों

बाक़ी पेज 11 पर

इस्लाम के बारे में पश्चिमी मीडिया द्वारा पैदा की गई गलतफहमियों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए युवा गैर-मुस्लिम महिलाओं ने टिक टोक पर कुछ मिनटों के लिए पवित्र कुरान का पाठ और कुरान की आयतों का अनुवाद सुना, इसका अध्ययन किया और तब उनकी समझ में आया कि वास्तव में पश्चिमी मीडिया लगातार इस्लाम और मुसलमानों के बारे में भ्रामक प्रचार और झूठ फैलाने में लगा हुआ था। जैसे ही इन युवा महिलाओं ने कुरान का अध्ययन किया, अल्लाह ने उनके लिए व्यापक सोच और व्यापक लेखनी बनाई, और उन्होंने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्य। करना शुरू कर दिया। इस संबंध में हैशटैग कुरान बुक क्लब के जरिए कई वीडियो अपलोड किए गए और इस ऐप पर 1.9 मिलियन व्यूज दर्ज किए गए। हालाँकि कुछ लोग पवित्र कुरान के ऑनलाइन पढ़ाई, कोई सोशल मीडिया पर कुरान की आयतें सुन रहा है तो कुछ ऐसे भी हैं जो काम पर जाते वक्त पवित्र कुरान की तिलावत सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। जिससे उन्हें पता चलता है कि पश्चिमी मीडिया जानबूझकर इस्लाम को बदनाम करने में लगा हुआ था।

इस्लामी दुनिया .....। इस्लामी दुनिया .....। इस्लामी दुनिया

भारत से क्यों दूर होने लगा मालद्वीव

हिंद महासागर में मालदीव भारत का एक अहम समुद्री पड़ोसी देश है। मालदीव की भौगोलिक स्थिति भारत की रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी के कारण मालदीव की अहमियत भारत के लिए और बढ़ गई है। पिछले कई वर्षों से भारत और मालदीव के संबंध गहरे रहे हैं। लेकिन मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा है।

मालदीव में वर्ष 2013 से 2018 के बीच अब्दुल्ला यामीन की सरकार रही और इस सरकार की करीबी चीन से थी। यामीन की सरकार के दौरान ही मालदीव चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना था। लेकिन 2018 में यामीन की सरकार गई और इब्राहिम मोहम्मद सालेह के नेतृत्व में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की सरकार बनी तो भारत के साथ संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। इब्राहिम सालेह ने अपनी विदेश नीति में भारत को तवज्जो देते हुए 'इंडिया फर्स्ट' की नीति अपनाई थी।

सालेह के नेतृत्व में मालदीव और भारत के बीच कई रक्षा और आर्थिक समझौते हुए। सालेह भारत के साथ गहरे संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध रहे, लेकिन भारत के साथ बढ़ती करीबी को मालदीव के विपक्ष ने सालेह सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने का हथियार बनाया। विपक्ष ने सालेह की 'इंडिया फर्स्ट' नीति के खिलाफ 'इंडिया आउट' कैंपेन चलाया। तब सरकार के आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत के साथ संबंधों में संप्रभुता को किनारे रखा जा रहा है और भारत के सैनिकों को मालदीव की जमीन पर रहने की अनुमति दी गई। जब सालेह सरकार ने भारत के साथ वर्ष 2021 में उथुरु थिला फलहु (यूटीएफ) समझौते पर हस्ताक्षर किया तो। विपक्ष और हमलावर हो गया। यह एक रक्षा समझौता था, जिसके तहत संयुक्त रूप से नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्पर बनाना था। मालदीव में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव हुआ और भारत विरोधी अभियान एक लोकप्रिय मुद्दा बन गया। कुछ ही महीनों में मोहम्मद मुइज्जू विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उभरे, क्योंकि कई मामलों के कारण पूर्व राष्ट्रपति यामीन चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। मुइज्जू राष्ट्रपति बनने से पहले मालदीव की राजधानी माले के मेयर थे। मुइज्जू ने मतदाताओं को लुभाने के लिए 'इंडिया आउट' कैंपेन का नेतृत्व किया। मुइज्जू ने यह भी वादा किया था कि वह सत्ता में आएंगे तो मालदीव की जमीन से भारतीय सैनिकों को हटाएंगे और भारत से व्यापारिक रिश्तों को भी संतुलित करेंगे। ऐसा कहा जाता था कि सालेह सरकार की व्यापार नीति भारत की तरफ झुकी हुई थी। मुइज्जू ने खुद के चीन परस्त होने के आरोपों को ख़ारिज कर दिया और खुद को मालदीव का राष्ट्रभक्त बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मालदीव में भारत या चीन के अलावा किसी भी देश के सैनिकों की मौजूदगी की अनुमति नहीं देगी। हालांकि, चीन के साथ मज़बूत संबंधों के संकेत वह दे चुके थे। मुइज्जू चाहते थे कि अगर उनकी सरकार बने तो चीन से आर्थिक मदद का फायदा सरकार को मिले।

पिछले साल सितंबर में 54 फीसद वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू को जीत मिली थी। नवंबर में मुइज्जू ने द्वीपीय देश मालदीव के आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनते ही संकेत दे दिया कि उनकी विदेश नीति में भारत से दूरी बनाना प्राथमिकता में है। उन्होंने पहला विदेश दौरा तुर्की का किया। मुइज्जू ने एक परंपरा तोड़ी, क्योंकि इससे पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का ही करता था। ❑❑

बांग्लादेश : शिकंजे में मसीहा

वर्ष 2006 में जब गरीबी के ख़िलाफ व्यापक अभियान चलाने के लिए मुहम्मद युनुस को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो बांग्लादेश में खुशी की लहर दौर गई थी और देश को गौरवान्वित करने वाले इस अर्थशास्त्री के सम्मान में सरकार ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तब भला कौन सोच सकता था कि एक दिनश्गरीबों का बैंकर कहे जाने वाले इस अर्थशास्त्री को उसी मुल्क के श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए छह महीने की जेल की सजा दी जाएगी। ऐसे यवत में जब देश में चुनाव होने वाले हैं, इस न्यायिक प्रक्रिया को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना अस्वाभाविक नहीं है। युनुस के समर्थक इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं, जबकि तथ्य यह है कि उनके खिलाफ देशभर में सौ से भी ज्यादा मामले चल रहे हैं और कई मामले उनके पूर्व सहयोगियों एवं कर्मचारियों ने ही दायर किए हैं।

प्रारंभिक जीवन

मुहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून, 1940 को तटीय शहर चटगांव के एक सफल स्वर्णकार परिवार में हुआ था। उन्होंने बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय से बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की और स्नातक के बाद वह फुलब्राइट छात्रवृत्ति मिलने पर अध ययन के लिए अमेरिका चले गए। 1970 के दशक की शुरुआत में यूनुस शुरुआत में यूनुस ने बेंडरचिल्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में अपनी पीएचडी पूरी की। बांग्लादेश के आजाद होने के तुरंत बाद वह अपने बतत लौटे और चटगांव विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाने लगे। यह वही दौर था, जब बांग्लादेश भीषण अकाल से जूझ रहा था। ऐसे में उन्हें विश्वविद्यालय की कक्षा में अर्थशास्त्र के सुरुचिपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाना मुश्किल लगा और अपने चारों तरफ भयंकर गरीबों को देखकर इस युवा-अर्थशास्त्री ने जमीनी स्तर पर तत्काल कुछ ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख उन्हें अपनी मां से मिली थी, जो अपने दरवाजे पर आए किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाती थीं। ग्रामीण बैंक की स्थापना उन्हें पता चला कि छोटे व्यवसायियों को आमतौर पर पारंपरिक बैंक ऋण नहीं देते या तो सीधे मना कर देते हैं या उनसे जबरन ज़्यादा ब्याज दरें बसूलते हैं। वर्ष 1976 में यूनुस ने 42 स्थानीय महिलाओं को बहुत छोटी रकम उधार दी, जिन्हें अपने व्यावसायिक उत्पादन के लिए सामग्री खरीदने की जरूरत थौ। यूनुस का मानना था कि गरीब व्यक्ति छोटे ऋण लेकर अपनी छोटी व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाकर गरीबी दूर कर सकता है। 1976 से 1983 तक पूनुस ने इसी तरह प्रायोगिक तौर पर अन्य बैंकों से पैसा उधार लेकर छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान किया और अंततः 1983 में औपचारिक रूप से ग्रामीण बैंक की स्थापना की। जून 2020 तक ग्रामीण बैंक ने 90 लाख से ज्यादा अत्यंत गरीब लोगों

बाक़ी पेज 11 पर

यह दिल्ली है .....। यह दिल्ली है .....। यह दिल्ली है

दिल्ली के स्टेशनों की कनेक्टिंग रोड होगी जाम □ी, शुरुआत निज़ामुद्दीन से

दिल्ली मंडल ने हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत स्टेशन की कनेक्टिंग रोड पर दोनों ओर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के साथ की गई है, ताकि स्टेशन तक यात्रियों की पहुंच सुगम व आसान हो और उनका समय भी बच सके। इसके अलावा कनेक्टिंग रोड के सौंर्य्यीकरण का काम भी किया जाएगा। निज़ामुद्दीन स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में प्लेटफार्म पर डिजिटल डिस्पले, पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अपग्रेडेशन, ग्रीन स्टेशन के लिए सोलर अपग्रेडेशन, मैकेनिकल सेनिटेशन सहित कई सुविध ाएं होंगी। दिल्ली मंडल ने अपने सभी रेलवे स्टेशनों की कनेक्टिंग रोड पर हो रहे अतिक्रमण को अलग-अलग फेज में हटाने की योजना बनाई है। पहले फेज में निज़ामुद्दीन, सब्जी मंडी, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार स्टेशन का कायाकल्प होगा। इसका फायदा प्रतिदिन करीब 4 लाख यात्रियों को मिलेगा।

एक बार में 5 से ज्यादा बसें खड़ी नहीं करने को कहा

रेलवे ने परिवहन विभाग को पत्र लिख कर स्टेशन परिसर में एक बार में 5 से अधिक बस खड़ी नहीं करने को कहा है। अभी यहां 12-15 बसें लगा दी जाती हैं, जिससे जाम लगता है। साथ ही कनेक्टिंग रोड पर सामान बेचने वालों से लेकर ऑटो-टैक्सी चालक खड़े हो जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को आने-जाने में काफी समय लग जाता है। इस समय को बचाने के लिए रेलवे ने कनेक्टिंग रोड से अतिक्रमण हटाने और रिंग रोड तक नई सड़क बनाने का फैसला किया है।

ज़मीन मिलने के बाद नई रोड बनाकर चारदीवारी की जाएगी

रिंग रोड से निज़ामुद्दीन स्टेशन तक एमसीडी की जमीन है। एमसीडी की ज़मीन होने के कारण रेलवे अतिक्रमण नहीं हटा सकती है। एमसीडी से फरवरी में जमीन मिलने की उम्मीद है, एमसीडी को आग्रह किया जाएगा कि जमीन अतिक्रमण मुक्त कर दें। एमसीडी से जमीन मिलने के बाद मार्च के अंत तक इस जगह नई रोड बनाकर सौंर्य्यीकरण कर दोनों तरफ चारदीवारी की जाएगी।

कनेक्टिंग रोड पर बने अवैध होटल, चाय की दुकानें और अन्य सामान विक्रेताओं को हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से कर दी गई है। हाल ही में भोगल की साइड कनेक्टिंग रोड पर से अतिक्रमण हटा गया है। अब सराय काले खां की साइड से हटाया जाना है। दरअसल, रिंग रोड से स्टेशन तक की जमीन एमसीडी की है। ऐसे में रेलवे ने एमसीडी से रिंग रोड से स्टेशन तक की 1100 स्क्वॉयर दर जमीन की मांग की है। रेलवे इसके बदले एमसीडी को कुतुबगढ़ में जमीन देगा। ❑❑

राजधानी में साढ़े आठ हजार पदों के लिए आवेदन मांगे

युवाओं के लिए दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का बेहतर अवसर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से लगातार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। बोर्ड ने अब तक की सबसे बड़ी चयन प्रक्रिया के तहत एक साथ साढ़े आठ हजार से अधिक खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। बोर्ड की तरफ से चार अलग-अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट www.dsssb.delhi.gov पद पर जाकर कर सकेंगे।

जिला एवं सत्र न्यायालय, परिवार न्यायालयः- पद-वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक, व्यक्तिगत सहायक और कनिष्ठ न्यायिक सहायक आवेदन-8 जनवरी से 8 फरवरी तक

ब्योरा आरक्षण के क्रम में

सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	कुल
296	300	152	115	127	990

टीजीटी के खाली पदः- विभाग-शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी और अन्य विषय-गणित, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कला और अन्य

आवेदन-8 फरवरी से 8 मार्च तक

ब्योरा आरक्षण के क्रम में

सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	कुल
2897	724	507	846	144	5118

मल्टि टॉस्किंग स्टाफः- विभाग-महिला एवं बाल कल्याण, समाज कल्याण, प्रमुख लेखा विभाग, विधानसभा, डीएसएसएसबी, योजना, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑडिट, कानून एवं न्याय व्यवस्था समेत 15 विभाग

आवेदन - 8 फरवरी से 8 मार्च तक

ब्योरा आरक्षण के क्रम में

सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	इंडब्ल्यूएस	कुल
253	183	31	40	60	567

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अन्य विभाग

ब्योरा आरक्षण के क्रम में:- पद- फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, कुक, ट्रांसलेटर, सेक्शन ऑफिसर आवेदन 13 फरवरी से 13 मार्च तक

सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	कुल
854	562	143	149	188	1896

संपादकीय

शांति मिशन

लोकतांत्रिक भारत में

महिलाओं के शोषण का अंतिम समाधान क्या है?

आज हमारे लोकतांत्रिक भारत में महिलाओं का शोषण कोई नई बात नहीं है। अखबारों के पन्ने हर दिन महिलाओं के शोषण और उनके खिलाफ यौन अपराधों की खबरों से भरे रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट हर साल आंकड़ों के साथ प्रकाशित होती है जो विशेष रूप से महिलाओं के शोषण की एक सतत श्रृंखला दिखाती है।

हाल ही में एक बार फिर छब्ठ (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) की महिलाओं की ताजा रिपोर्ट सामने आई है बढ़ते अपराधों की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में महिलाओं के ख़िलाफ आपराधिक घटनाओं के 445,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में यह संख्या 428,278 और 2020 में 3,000,503 थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध की ये घटनाएं 2021 की तुलना में लगभग चार प्रतिशत अधिक हैं। आंकड़े बताते हैं कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं के ख़िलाफ अपराधों में सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में हुई है, जबकि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर सबसे ज्यादा है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा हैं आईआर दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली उन्नीस मेट्रो शहरों में लगातार तीसरे साल शीर्ष पर है। सभी राजनीतिक दल चुनावों में घोषणा करते हैं कि वे सत्ता में आने के बाद हर स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे मे। एनसीआरबी के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध न बढ़े हों। विडंबना यह है कि महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराधों में पति, प्रेमी, रिश्तेदार या अन्य करीबी लोग शामिल होते हैं। इन मामलों में, 31: महिलाओं के साथ उनके पतियों या रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। 1902: अपहरण, 1807: बलात्कार के प्रयास और 80: बलात्कार। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में रेप के कुल 31 हजार 516 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा राजस्थान में 3 हजार 399 मामले, उत्तर प्रदेश में 3 हजार 690 मामले, मध्य प्रदेश में 3 हजार 29 मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र में 904 मामले और हरियाणा में 1,778 मामले सामने आए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में देश की राजधानी दिल्ली देश में शीर्ष पर है, 2022 में महिलाओं के खिलाफ चौदह अपराध होंगे।

एक हजार 247 मामले दर्ज किये गये जहां दिल्ली और राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य हैं, वहीं धर्म के नाम पर जान देने वाली महिलाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश पहले और बिहार दूसरे स्थान पर है। धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में 2 हजार 138 और बिहार में 1 हजार 57 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जबकि मध्य प्रदेश में 518, राजस्थान में 451 और दिल्ली में 131 महिलाओं की हत्या कर दी गई। छब्ठ के अनुसार, प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2021 में 6405: से बढ़कर 2022 में 66: हो गई है, जिसमें से 2022 के दौरान उन्नीस मेट्रो शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। अपराध के कुल 48 हजार 755 मामले दर्ज किये गये। ये 2021 के 43 हजार 414 मामलों से 1203: ज्यादा हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम दावों, वादों और नारों के बावजूद देश में ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। भारतीयों की स्थिति कितनी चिंताजनक है जिस संस्कृति में महिलाओं को देवी माना जाता है, वहां महिलाएं खुद अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, सम्मान हत्या और सहवास की घटनाओं के मामले में स्थिति काफी दर्दनाक है। यह कुछ हद तक विडम्बनापूर्ण है कि महिलाएं बाहरी वातावरण, यहां तक कि अपने परिवार और अपने पड़ोस में भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 19 सितंबर 2023 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 20,693 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि उपरोक्त वर्ष के अंत तक काफी बढ़ गई हैं। वर्ष 2022 में आयोग को 1,957 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो 2014 के बाद से सबसे अधिक थीं। 2014 में आपको 1,906 शिकायतें मिलीं, जबकि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 1,000 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। कुल 24 श्रेणियों में कमीशन एसिड अटैक, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, दहेज से संबंधित मौत, यौन शोषण और बलात्कार आदि जैसी शिकायतें दर्ज की गईं। दायर की गई अधिकांश शिकायतें सम्मान के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं, इसके बाद घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न। कर्ण, दुर्व्यवहार की शिकायतें हैं महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कानून सख़्त किए गए, उससे लगा कि समाज इस तरह के त्यों के प्रति अधिक संवेदनशील और संलिप्त होगा।

असामाजिक तत्वों का मनोबल कम हो लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने न आती हों। ऐसी कई घटनाओं में पुलिस प्रशासन का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार भी देखने कौ आता है। यह निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को शायद ही कोई डर महसूस होता है। सख्त कानूनों, महिला सुरक्षा के नाम पर उठाए गए तमाम कदमों और आधी दुनिया की अस्मिता को लेकर समाज में बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद आखिर क्या कारण हैं कि बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न या अपहरण के मामले भी सामने आते रहते हैं? और आधी दुनिया के खिलाफ अपराधों का सिलसिला रोकने के लिए नाम नहीं मिल रहा।

दरअसल, इसका मुख्य कारण यह है कि सख्त कानून होने के बावजूद असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जाहिर है कि सिर्फ कानून सख्त कर देने से महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता, ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वह अपनी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त और जवाबदेह बनाए। पुलिस प्रशासन की जो स्थिति है। इन अपराधों के लिए बेनकाब हो चुके लोग काफी हद तक जिम्मेदार हैं। ऐसे में पुलिस पीड़ित को प्रताड़ित कर उस पर नमक कैसे छिड़क सकती है। ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहते हैं कि किस तरह परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी लोगों के दिलों में पुलिस और कानून का डर पैदा किया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कैसे कम किया जा सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर राज्य और केंद्र सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।❑❑

तारीख़े इस्लाम

सिरतुन्नबी स.अ.स. पर लिखी गई सबसे तफ़्सीली किताब

अर-रहीक़ुल मख़्तूम

लेखक: मौलाना सफीउर्रहमान मुबारकपुरी किस्त 38

फिर हम बनू साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की धरती का कोई भाग हमारे इलाक़े से ज़्यादा भुखमरी का शिकार था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जातीं तो पेट भरी हुईं और दूध से भरपूर वापस आतीं। हम दूहते और पीते, जबकि किसी और व्यक्ति को दूध की एक बूंद भी नसीब न होती। इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही न था, यहां तक कि हमारी क़ौम के लोग अपने चरवाहों से कहते कि भाग्यहीनो ! जानवर वहीं चराने ले जाया करो, जहां अबू जुवैब की बेटी का चरवाहा ले जाया करता है-लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आतीं। उनके अन्दर एक बूंद दूध न रहता, जबकि मेरी बकरियां पेट भरी और से दूध भरपूर वापस आतीं। इस तरह हम अल्लाह की ओर से बराबर बढ़ोत्तरी और भलाई देखते रहे, यहां तक कि इस बच्चे के दो साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया।

यह बच्चा दूसरे बच्चों के मुक़ाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि दो साल पूरे होते-होते वह कड़ा और गठीला हो गया। इसके बाद हम इस बच्चे को उसकी मां के पास ले गए। लेकिन हम उसकी जो बरकत देखते आए थे, उसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वह हमारे पास रहे, चुनांचे हमने उसकी मां से बातचीत की।

मैंने कहा, क्यों न आप मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि जरा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे उसके बारे में मक्का की महामारी का खतरा है। गरज हमारे बराबर आग्रह पर बच्चा उन्होंने हमें वापस दे दिया।

सीना खुलने की घटना

इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दूध पिलाने की मुद्दत खत्म होने के बाद भी बनू साद ही में रहे, यहां तक कि जन्म के चौथे या पांचवें साल मुबारक सीना चाक किए जाने की घटना घटी। इसका पूरा विवरण हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत में मिलता है, जो सहीह मुस्लिम में अंकित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्रील ने आपको पकड़ कर पटका और सीना चाक करके दिल निकाला, फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, यह तुमसे शैतान का हिस्सा है, फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और फिर उसे जोड़ कर उसकी जगह लौटा दिया, इधर बच्चे दौड़ कर आपकी मां अर्थात दाई के पास पहुंचे और कहने लगे, मुहम्मद कत्ल कर दिया गया, उनके घर के लोग झट-पट पहुंचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था।

मां की गोद में

इस घटना के बाद हलीमा को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने आपको आपकी मां के हवाले कर दिया, चुनांचे आप छः साल की उम्र तक मां ही की गोद में पलते रहे।

उधर हज़रत आमिना का इरादा हुआ कि वह अपने मृत पति की याद में यसरिब जाकर उनकी क़ब्र की जियारत करें, चुनांचे वह अपने यतीम बच्चे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अपनी सेविका उम्मे ऐमन और अपने गार्जियन अब्दुल मुत्तलिब के साथ कोई पांच सौ किलोमीटर की दूरी तै करके मदीना तशरीफ ले गईं और वहां एक महीने तक ठहर कर वापस हुईं, लेकिन अभी रास्ते ही में थीं कि बीमारी ने आ लिया। फिर यह बीमारी तेजी अख्तियार कर गई, यहां तक कि मक्का और मदीना के बीच अबवा नामी स्थान पर पहुंच कर वफात पा गईं।

इंटरव्यूह ..... इंटरव्यूह

खाद्य तेलों के दामों में फिलहाल दिख रही है, नर्मी, सीलिंग, जीएसटी पर व्यापारियों को मिल रही राहत

सुनील कुमार

सवालः- वैश्विक बाज़ार में तेल के हालात को देखते हुए आगे बाज़ार को कैसे देखते हैं ?

जवाबः- वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें घट रही हैं और वहां अगर दाम कम हैं तो भारत में तेल सस्ते में बिकते हैं तो स्थानीय बाजार में सस्ते में बिकेगा।

सवालः- सस्ता तेल अगर होगा तो क्या किसानों को फसल का पूरा लाभ मिलेगा, या उनके लिए यह नुकसानदेह होगा ?

जवाबः- बिल्कुल यह किसानों के लिए नुकसानदेह है, कई बार किसानों को समर्थन मूल्य से कम फसल का दाम मिलता है। भारत में 240 लाख टन खाद्य तेल की खपत है, जिसमें 65 से 70 फीसद इंपोर्ट करते हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम, शिकागो, अंर्जेंटीन से सोयाबीन का तेल आता है। हमारी खपत का सिर्फ 35 फीसद उत्पादन यहां होता है। चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम या फ्री होती है तो इंपोर्ट भारी मात्रा में होता है। सोयाबीन। हमारे देश में भी होता है और लेकिन कंप्टीशन में भारत के माल की कीमत उसी अनुपात में मिलती है जो कि कई बार कम होती है। अब, अगर वैश्विक बाज़ार में दाम कम हैं तो उसे वह दाम नहीं मिल पाते। इससे किसान हतोत्साहित हो जाते हैं, इसका असर अगले साल तब दिखता है जब वह दूसरी फसल करता है। तब बाज़ार का रूख़ बदल जाता है।

सवालः- विदेशी बाज़ार में तेल के दामों में कमी आई है तो क्या इसका असर दिल्ली या भारत के बाज़ार में भी दिख रहा है?

जवाबः- इसी तरह अगर कम दरों पर इंपोर्ट होता रहा तो असर दिखेगा। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट हो रहा है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि हर महीने की जरूरत के अनुसार इंपोर्ट हो। कई बार पोर्ट पर बहुत ज्यादा माल होता है तब दाम और गिर जाते हैं। हां, उपभोक्ता के लिए दाम काबू में इस पिछले डेढ़ साल में रहे हैं। लेकिन किसान को नुकसान ज़रूर होता है।

सवालः- तेल के बाज़ार में अभी दुनिया भर में क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं और अगले 3 महीने में दामों को आप किस तरह देखते हैं ?

जवाबः- वैश्विक बाज़ार के फ्यूचर ट्रेड में तीन महीने में आज के दाम पर ही व्यापार दिखा रहे हैं, इससे लगता है कि न तो मंदा होगा और न ही ज्यादा महंगा होगा। स्थानीय कारणों में देखें तो भारत में अक्तूबर, नवम्बर में मूंगफली, सोया और बिनौला की फसलें आ गई हैं और बाजार में उनका दबाव है। सबसे बड़ी फसल सरसों की है वह भी फरवरी में आ रही है। उसका दबाव भी दामों में कमी दिख सकता है। अभी चौतरफा यही आसार हैं कि दाम स्थिर रहेंगे। हांलाकि अभी दाम इतने नीचे हैं कि इससे कम गिरने की संभावनाएं ज्यादा नहीं हैं। पिछले डेढ़ साल में बात करें तो मई-2022 से दिसम्बर-2023 तक खाद्य तेल करीबन 40 प्रतिशत कम हुए हैं।

भारत में 240 लाख टन खाद्य तेल की खपत है, जिसमें 65 से 70 फीसद इम्पोर्ट करते हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम, शिकागो, अर्जेंटीन से सोयाबीन का तेल आता है। हमारी खपत का सिर्फ 35 फीसद उत्पादन यहां होता है। चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम या फ्री होती है तो इम्पोर्ट भारी मात्रा में होता है। सोयाबीन हमारे देश में भी होता है लेकिन कंप्टीशन में भारत के माल की कीमत उसी अनुपात में मिलती है जो कि कई बार कम होती है।

सवालः- -(बीच में काटते हुए) रिटेल में तो यह राहत नहीं दिखती?

जवाबः- पैक्ड खाद्य तेल की एमआरपी को लेकर हमनें कई बार सरकार से कहा, वह बहुत ज्यादा प्रिंटेड होती है। चौतरफा दाम जब गिरते हैं तो थोक में तुरंत गिर जाते हैं लेकिन रिटेल में धीमी गति से होता है जिससे रिटेल बाजार में लाभ देर में पहुंचता है।.चीन का इस बाजार में अभी क्या दखल है?

सवालः- चीन से जो माल भारत आता था अब वह भी उस मात्रा में नहीं है। दीपावली पर माल की बहुत कम खरीदारी हुई है। चीनी माल भारतीय उत्पाद से कम कीमत में आकर बिकता है। भारत के माल की मांग बढ़ी है कई व्यापारियों ने भी इस दिशा में पहल की है।

सवालः- दिल्ली के व्यापारियों को जीएसटी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्या मुद्दा है यह?

जवाबः- व्यापारियों के पास 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी नोटिस आ रहे हैं। इसमें ट्रेडर्स से उनके पुराने रेकॉर्ड्स का हिसाब-किताब मांगा जा रहा है। आजकल कंप्यूटर का जमाना है। तुरंत पुराना डेटा मिल जाता है। अब किसी व्यापारी ने 5 साल पहले किसी से बिजनेस किया है, बाद में उसने कारोबार छोड़ दिया या उसका जीएसटी नंबर कैंसल हो गया। उसने टैक्स नहीं जमा कराया, तो दूसरा व्यापारी कैसे जिम्मेदार होगा ? अब तक 17 हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार के स्तर पर 1200 बार संशोधन किए हैं और अब उनको लेकर चूक होनी संभव है। सरकार को व्यापारी के साथ सौहार्दपूर्ण रवैया रखना चाहिए।

बाक़ी पेज 11 पर

अब तो सारी क्षेत्रीय ज़बानें ही ख़तरे में हैं

सादिक़ा नवाब सहर

2023 के लिए उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब सहर को दिए जाने की घोषणा हुई है। देश की गंगा जमुनी तहजीब को सबसे ख़ास मानने वाली सादिका नवाब को यह पुरस्कार उनके उर्दू उपन्यास 'राजदेव की अमराई' के लिए दिया जाएगा। पेश हैं उनसे हुई एक बातचीत के अहम अंशः-

सवालः- अपने उपन्यास 'राजदेव की अमराई' में आप ब्राह्मण संस्कृति का बारीक नक्शा पेश करती है। एक मुस्लिम अफसानानिगार ब्राह्मण संस्कृति को पेश करती हो, ऐसा पहले नहीं देखा?

जवाबः- हम एक छोटी सी जगह खोपोली में हैं। अगर हम मुंबई में होते तो हमें ये मौके शायद न मिलते। हमारे आसपास माथेरान पहाड़ी के आदिवासी भी बसंते हैं। दलित, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सभी है। जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वे हमारे बहुत बड़े टीचर होते हैं। हमने ब्राह्मण समुदाय को भी खूब अच्छी तरह जाना, उनके घरों में हमारा आना-जाना बहुत रहा। चिपलून के क्षेत्र परशुराम में ब्राह्मण हैं, उनके यहां भी हम खूब आए-गए हैं। हमारे बहुत से दोस्त है। इस वजह से हो लिख पाई। वैसे मैंने अलग-अलग समुदायों के बारे में भी कहानियां लिखी है। मैं किसी एक विषय तक सीमित नहीं रहती। चाहती हूं कि हर तरह के लोगों से जुड़ी रहूँ, हर एंगल से दुनिया देखें। हम गंगा-जमुनी तहजीब में रहते हैं, उसे फॉलो करते हैं। इस नॉवेल का किरदार ब्राह्मण ही था तो शुरू से उसी के इर्द-गिर्द पूरी कहानी रची है। एक कहानी ऐसी भी लिखी थी, जिसमें लड़की ब्राह्मण से ईसाई हो जाती है, फिर उसकी ज़िंदगी में कैसी-कैसी चुनौतियां आती है।

सवालः- आज बहुत से राजदेव है हमारे बीच, जो अपना गांव छोड़ कर शहर में पैसे कमाने के लिए भटक रहे हैं। पलायन भारत में एक गंभीर समस्या है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है?

जवाबः- यह मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता। हर इंसान को हक है कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर करे। इसी चाह में तो वह भागता है। सरकार अपने काम करती रहती है। लेकिन हमारा मुल्क आजाद हुए बहुत साल नहीं हुए हैं। वैसे भी पलायन हर मुल्क में है। यहां तक कि जापान और चीन में भी इसे देखा जा सकता है। अमेरिका में भी कुछ इलाकों में पलायन है। कुछ हिस्से हर मुल्क में ऐसे होते हैं, जिन पर रोशनी पड़ने की जरूरत होती है।

सवालः- आपकी कहानी कहती है कि रिश्तों में औरतें स्वार्थी हो रही हैं। क्या यह औरत की दुनिया का पूरा सच है?

यह औरत की दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है। पहले औरत को पता नहीं था अपने बारे में। उसको जो डिक्टेशन दिया गया था, उसी पर यो चलती थी। अब औरते पढ़ रही है तो उसमें बराबरी का अहसास आ रहा है। से सवाल उठा रही है। यह औरत के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन कभी फैमिली टूट जाती है तो बच्चे को उसका नुकसान भी होता है।

सवालः- आगाज़ उर्दू से की, फिर आप हिंदी की विभाग प्रमुख हुई। अंग्रेजी का अध्ययन किया लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको उर्दू के लिए मिला। आपको क्या लगता है उर्दू में ज़्यादा मकबूलियत मिली या हिंदी में...?

जवाबः- यह सच है कि आगाज़ उर्दू से हुआ। असल में बचपन से उर्दू में लिखा। फिर मेरे लिए जो बेहतर था, किस्मत उस ओर ले आई मुझे। मैं हिंदी की खिदमत करने लगी। वैसे मेरा सारा ही काम उर्दू में है। पहले मेरी किताबें उर्दू में आई, फिर हिंदी में तर्जुमा हुआ। राजदेव की अमराई भी 2019 में पहले उर्दू में ही आई। हिंदी में तो 2023 में आई है।

सवालः- आप ने गज़लें भी लिखीं और उपन्यास भी। दोनों में किसको अपने ज़्यादा क़रीब पाती है?

जवाबः- ये दोनों चीजें जो हम लिखते हें यह हमारा इज़हार हैं मेरे लिए दोनों ही ज़रूरी रहा। जब कभी बहुत मसरूर रही, कम अल्फाज़ों में अपनी बात कहती रही तो वह गज़ल होती रही। वे भी बहुत खूबसूरत दिन थे। बाद में जब अफसाने लिखने लगी तोवो भी खूबसूरत वक़्त रहा। शायरी मेरे अंदर बसी लेकिन अब फिक्शन को ज़्यादा एन्जॉय करती हूं। जब से मैंने फिक्शन पर तवज्जोह ज़्यादा देनी शुरू किया, मेरा समाज के बारे में आब्जर्वेशन ज़्यादा बढ़ गया है।

सवालः- लोग कहते हैं कि जब तलक उर्दू की चीजें हिंदी में नहीं आतीं, वो इतनी मकबूल नहीं होतीं..

जवाबः- ऐसा नहीं है। उर्दू में ही हमारी किताबें बहुत दूर तक पहुंच चुकी थीं। मुल्क से बाहर भी पहुंचीं। तभी तो हमें अंदाजा लगा कि ये काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है।

सवालः- क्या आज उर्दू सिमटती जा रही है?

जवाबः- ऐसा नहीं है। पहले जितने उर्दू के स्कूल होते थे, अब उससे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा हैं उर्दू स्कूल। ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन कुछ और चीजें भी होती हैं जो साथ-साथ चलती हैं। इस जुबान को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि यह दूसरी जुबानों में भी मर्ज हो जाती है। दूसरी जुबानों में जब मर्ज़ होती है तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। मुझे नहीं लगता कि उर्दू कभी सिमट सकती है। मेरे ख़्वाबों-ख़्यालों में भी दूर तलक कहीं ऐसा नज़र नहीं आता।

सवालः- रोज़गार से जो जुबान सिमट जाती है वह समाज से भी कट जाती है, ऐसा कहा जाता है। आज के दौर में आप इसे कैसे देख रही हैं?

जवाबः- उर्दू क्या, सारी जुबानों का यही हाल है। जितनी भी वर्नाक्युलर जुबानें हैं, सबका यही हाल है। हिंदी हो, मराठी हो इस मामले में सबका हाल एक जैसा, सब इंग्लिश की ओर भाग रहे हैं। लोगों को लगता है यह बड़ी नेमत है। सारी जुबानें खतरे में हैं अब तो। लेकिन एक न एक दिन लोगों को अपनी जुबान की तरफ लौट कर आना पड़ता है, उसकी मोहब्बत वापस खींच लाती है।

सवालः- उर्दू लेखन का भविष्य क्या है? उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत है?

जवाबः- हमारे यहां महाराष्ट्र में तो उर्दू के लिए सरकारी कोशिशें बहुत अच्छी हैं। तमाम निजी संस्थान भी उर्दू फैलाने के लिए काम कर रहे है। मैं खुद फ्री उर्दू क्लासेज 1992 से चला रही हूं। ❑❑

मिज़ान ..... रूपरेखा वर्मा

बिलकिस केस में कोर्ट के फैसले ने इसाफ़ को मज़बूती दी है

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानून में आस्था को बहाल किया है। बिलकिस बानो के साथ किए गए अपराध के दोषियों की जिस तरह से सज़ा ख़त्म की गई, वह देश के कानून के खिलाफ था। जब कानून-व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार अंग कानून तोड़ते हैं तो देश पर उसके रूपरेखा वर्मा प्रभाव गहरे और दूरगामी होते हैं। इससे कानून, सरकार और व्यवस्था में लोगों की आस्था कम होती है।

अहम फैसला : इधर, लंबे वक्त से बहुत से लोग अदालतों से भी निराश हो रहे थे। अदालतों से हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, ऐसा बहुत से लोग महसूस करने लगे थे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के इस फैसले से न्यायालय में जनता की आस्था की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है। यही नहीं, इस फैसले का महत्व इसके साहसपूर्ण तेवर और इसके नैतिक विश्वास में भी है।

जवाब में देरी : बिलकिस केस में 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने खत्म की थी। जब यह मामला कोर्ट में आया, तो शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। उसने जवाब काफी देर से दिया, लेकिन उनके जवाब में यह दर्ज था कि इस बारे में उन्होंने केंद्र सरकार से भी मंजूरी ली हुई है। ऐसे में दोनों ही सरकारें। कहीं न कहीं इस मामले में कानून के खिलाफ काम करती पाई जाती है।

तथ्य छिपाए : जजमेंट में भी लिखा है कि जब उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में निर्णय लेने की परमिशन ली थी, तब बहुत से तथ्य छिपाए थे। फैसले में यहां तक लिखा । गया है कि गुजरात सरकार की इन अपराधियों के साथ सांठगांठ रही है। अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। लेकिन इस बात को जजों ने पकड़ा और शीर्षतम न्यायालय से यह बात आई, इसे सही किया गया, ये सभी बिंदु महत्व रखते हैं।

दोषियों का सम्मान : यह सोचकर ताज्जुब होता है। कि आज के दौर में भी किसी देश में उन लोगों की आरती उतारी जा सकती है, उनके पांव छुए जी सकते हैं और उन्हें मालाएं पहनाई जा सकती है, जो दुनिया में जघन्यतम माने जाने वाले दो-दो अपराधों के दोषी सिद्ध हुए हों-हत्या और बलात्कार।

बदले की भावना : यह कैसी मानसिकता है? असल में जब सांप्रदायिकता या जातिवाद का नहर लोगों के दिलों में । इतना गहरा बैठा दिया जाता है कि उसका विवेक पूरी तरह । मर जाए तो सिर्फ एक ही बात उनके ध्यान में रहती है कि कुछ लोग उनके दुश्मन हैं। उनसे बदला लो। बदले की इस प्रक्रिया में स्त्री हमेशा आसान लक्ष्य रही है।

स्त्री की देह : एक बात बहुत पहले से कही जाती रही है - कि हर युद्ध स्त्री की देह पर लड़ा जाता है। घृणा का युद्ध हो या परिवारों का, देशों का युद्ध हो या कौमों का, आप देखेंगे कि हमेशा औरतों की देह पर लड़ा जाता है। एक भावना मन में भरी है कि औरत किसी परिवार या समुदाय की इज्जत मानी जाती है, तो उस पर हमला करने से हम सबसे बड़ी तकलीफ पहुंचाएंगे। इन लोगों ने यह तकलीफ पहुंचाई, एक अलग धर्म की स्त्री के साथ अपराध किया। कुछ लोगों के मन में भरी घृणा के चलते उन्हें ऐसा घृणित अपराध भी स्वीकार्य लगने लगता है। उनमें से बहुतों को ऐसे लोग सम्मान करने लायक भी लगते हैं।

सोच पर असर : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह उम्मीद तो रखनी चाहिए कि उनकी सोच पर कुछ असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। मेरा मानना है कि उन्हें इस सोच को बदलना चाहिए, यह हमारी एक आदर्श कल्पना है।

कानून और नैतिकता : मुझे कानून ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अभी जितना पता चला है, उस हिसाब से अगर दोषियों की रिहाई महाराष्ट्र की उस कोर्ट की मंजूरी से होती तो शायद कानूनी दोष न निकलता। लेकिन नैतिक दृष्टि से वह हर हाल में गलत होता, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े दुष्कर्म में सज़ा कठोरतम ही होनी चाहिए। अगर नैतिकता की मांग यह है कि इसकी सज़ा कठोरतम होनी चाहिए तो उस सजा को कम करने के लिए कानूनी प्रावधान करना भी अनैतिक ही होगा।

माफ़ी का शास्त्र : पहले भी राजनीतिक और अराजनीतिक रूप से माफियां मिलती रही हैं। कानून में है कि अगर अपराध बहुत बड़ा नहीं है, अच्छा व्यवहार है, पछतावा है, तो माफी मिल सकती है। हो सकता है कि आप उससे लिखित में कुछ वादे करा लें, फिर सजा कम करें। लिखित चीजों के उल्लंघन करने पर आप फिर पकड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सजा कम करने का प्रावधान अपने आप में अनैतिक है। लेकिन अगर

बाक़ी पेज 11 पर

रोज़गार .....

युवाओं के लिए 'ईको फ्रेंडली' कैरिअर

आजकल हरे रंग की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां १२ सड़कों पर खूब दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस रंग की नंबर प्लेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होती हैं, जो एन्वॉयरन्मेंट फ्रेंडली होते हैं। यही वजह है कि इन गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से इसे भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है।

क्यों बढ़ रही है मांग

इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों और प्रणालियों के निर्माण क संयोजन के लिए मशीनिस्ट, वेल्डर, फैब्रिकेटर तथा औद्योगिक श्रमिकों की उच्च मांग है।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सेल्स मार्केटिंग, फाइनेंस के लिए पेशेवर प्रोफेशनल की डिमांड है।

चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, रखरखाव, पावरलाइन बिछाने और ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सिविल इंजीनियरों की मांग बढ़ रही है। बैटरी, रिचार्जिंग तकनीक आदि में सुधार करके इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है।

कोर्स और प्रवेश परीक्षाएं

फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर आदि के तौर पर काम करने के लिए कक्षा दसवीं या बारहवीं के बाद आईटीआई में दाखिला ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करना बेहतर विकल्प है।

मार्केटिंग में जाने के लिए आप किसी भी विषय से 12वीं करने के बाद बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के लिए भौतिक, रसायन और गणित विषय के साथ 12वीं में जेईई मेन और एडवांस की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना मनपसंद क्षेत्र चुन सकते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल डिजाइन के क्षेत्र में कॅरिअर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 12वीं के बाद एनआईडी, अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिजाइन (न्ब्म्क) की परीक्षा देकर बैचलर इन प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं।

ईवी मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों में हैं अवसर

हीरो इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, हुंडई, ओला इलेक्ट्रिक आदि प्रमुख ईवी मैन्युफैक्चरर्स कुशल पेशेवरों को अपनी कंपनी में काम दे रहे हैं और अच्छी सैलरी भी।

इतनी होगी कमाई

10वीं पास से लेकर बीटेक युवाओं के लिए इस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के अवसर मौजूद हैं। आप अपनी योग्यता और पदानुसार 15 हजार से लेकर 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह कमा सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ- साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी।

सिविल इंजीनिरिंग में बढ़े हैं अवसर

सवालः- मैं बीटेक सिविल से कर रही हूं। क्या यह ब्रांच ठीक है? कृपया मार्गदर्शन करें। सुनयना प्रसाद...

जवाबः- यह सही है कि एक समय में बीटेक सिविल इंजीनियरों के लिए अवसरों की कमी थी, परंतु आज इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए अवसरों में खासा इजाफा हुआ है। बीटेक सिविल के बाद जहां एक ओर आपके पास सरकारी नौकरियां भी हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े रियल एस्टेट दिग्गज सिविल इंजीनियरों की निरंतर नियुक्ति करते रहते हैं। यदि आप यूपीएससी के माध्यम से उत्कृष्ट सेवा में जाना चाहते हैं, तो बीटेक के बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में प्रवेश कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रतिष्ठानों, डिफेन्स और निजी क्षेत्रों में अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। देश की दिग्गज कंपनियां, जैसे टीसीएस, एल एंड टी, एनसीसी, इंडियन ऑइल, रिलायंस, टाटा स्टील, गोदरेज, लोधा, वाईजैग स्टील जैसी देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में सिविल इंजीनियर की नियुक्ति होती रहती है। अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी शुरू कर सकते हैं। सिविल के अच्छे जानकारों की मांग श्भारत से लेकर गल्फ देशों तक लगातार बनी रहती है।

सवालः- मैं जज के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हूं। अभी लॉ में प्रवेश तो तैयारी कर रही हूं। इस क्षेत्र में करियर बनाने की क्या प्रक्रिया है?

जवाबः- लॉ के छात्रों के लिए जज बनना किसी सपने के सच हो जाने से कम नहीं। देश के सभी राज्यों में स्थित सिविल कोर्ट न्यायालयों में जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रति वर्ष नियुक्तियां निकाली जाती है। यदि आप भी इसस क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, तो आपको दो योग्यता पूरी करनी होंगी। पहली, लॉ की डिग्री हासिल करनी होगी, जिसके अंतर्गत आप 10़2 के बाद 5 वर्षीय इंटिग्रेटेड लॉ पाठ्यक्रम या ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्षीय एलएलबी डिग्री हासिल कर सकती हैं। और दूसरा, लॉ की डिग्री के बाद बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करना होगा। यह परीक्षा आपको भारत में एक अधिवक्ता के रूप में काम करने की कानूनी योग्यता प्रदान करती है और इस परीक्षा के स्कोर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन बार काउन्सिल ऑफ इंडिया में एक अधिवक्ता के रूप में होता है। इन दोनों योग्यताओं को प्राप्त करने के साथ ही अब आप जज बनने के लिए प्रवेश जांच परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाती हैं।

विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित 'स्टेट जुडिशल सर्विस परीक्षा' के कुल तीन चरण होते हैं - प्रिलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू। परीक्षा में मूलतः सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व करेंट अफेयर्स, बेसिक रीजनिंग, इंडियन पेनल कोड, सिविल व क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट व एविडेंस लॉ इत्यादि विषय शामिल किए जाते हैं। चयनित आवेदकों की प्रारंभिक नियुक्ति मुनसिफ या जूनियर सिविल जज के तौर पर होती है, जिनको बाद में प्रोन्नत्ति प्रदान की जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी मैटीरियल आपको बाजार से उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र व सुझाव से आपको तैयारी करने की रणनीति बनाने में आसानी होगी।

इस्लामी दुनिया

भारत-बंगलादेश सीमा पर 3 करोड़ का सोना ज़ब्त

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत- बंगलादेश सीमा पर 3.09 करोड़ रुपए मूल्य की सोने की छड़ें और ईंटें जब्त की गईं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंगरेल सीमा चौकी क्षेत्र के हलदरपारा से बीएसएफ ने 4. 82 किलोग्राम वजन की सोने की 2 छड़ें और सोने के - 30 बिस्कुट ज़ब्त किए हैं। सीमा की सुरक्षा कर रहे जवानों ने इचामती नदी में 3 व्यक्तियों को देखा, जो भारत में आ रहे थे।

चुनाव अभियान शुरू करें उम्मीदवार : इमरान

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी पार्टी के उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे शांतिपूर्वक चुनाव अभियान की शुरुआत करें अन्यथा आठ फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए उनके टिकट रद कर दिए जाएंगे। जियो न्यूज की एक खबर के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने 'सिफर' मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल में संवाददाताओं से बातचीत में यह बयान दिया।

इजराइल के इनकार से बढ़ेगा ख़तरा : गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने इजराइल को आगाह किया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का द्वि-राष्ट्र समाधान से इनकार यकीनन संघर्ष को बढ़ाएगा जो पहले ही वैश्विक शांति के लिए ख़तरा है और हर कहीं अविवादियों का साहस बढ़ा रहा है। गुतारेस ने इजराइल हमास युद्ध पर अपनी अब तक की सबसे सख्त भाषा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा कि एक पूर्ण स्वतंत्र देश का निर्माण करना फलस्तीन के लोगों का अधिकार है और सभी को इसे मान्यता देनी चाहिए।

बैरिकेड्स तोड़े, कानून नहीं : राहुल भीड़ उकसाई : हिमंता बिस्वा

राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब गुवाहाटी पहुंची, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हमनें बैरिकेड्स तोड़े हैं लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते। हम जल्द ही असम में बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।

महान गणतंत्र दिवस को सलाम

लीजिये हमने लोकतंत्र के साये में एक साल पूरा कर लिया। भारत में गणतंत्र के क़याम पर पूरे 74 बरस गुज़र चुके और जिस वक्त आप ये पंक्तियां पढ़ रहें होंगे हमारी लोकतांत्रिक सरकार इंडिया गेट के लान पर लोकतांत्रिक समारोह मनाने में व्यस्त नज़र आ रही होगी।

26 जनवरी भारत के लिये एक ऐतिहासिक और यादगार दिन है आज से चौहत्तर साल पहले हमने भारत के लोकतांत्रिक सेकुलर देश होने का ऐलान किया था और संवैधानिक तौर पर यह ज़िम्मेदारी क़बूल की थी कि इस देश में धार्मिक आज़ादी तहजीबी तालीमी हक़ूक की पासबानी जायदाद के हक़ूक और न्याय प्राप्त करने का संवैधानिक हक़ हर भारतीय को है चाहे इसका सम्बन्ध किसी भी धर्म व कल्चर से हो, बराबर हक़ रहेगा। अल्पसंख्यकों को खासतौर से विश्वास दिलाया गया कि इनके दीन मज़हब पहचान की हर कीमत पर रक्षा की जायेगी। लेकिन यह बात अफसोस के साथ ही नोट की जायेगी कि आजादी और लोकतंत्र का 74 साल का लम्बा अरसा गुज़र जाने के बावजूद आज ये सब बातें जुबानी जमा खर्च से ज़्यादा मालूम नहीं होती। आज डंके की चोट पर इंसानों विशेषकर अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के अधिकारों पर जिस तरह हमला किया जा रहा है इसकी मिसाल किसी आजाद तो क्या किसी गुलाम देश में भी आसानी से नहीं मिलेगी। लोकतंत्र और साम्प्रदायिकता दो विपरीत वस्तुयें हैं लेकिन भारत में गत चौहत्तर सालों में साम्प्रदायिकता जिस तरह बड़ी और सरकारी स्तर पर इसकी जिस तरह हौसलाअफजाई की जाती रही है इसने यह साबित कर दिया है कि हमारे शासकों और देश के बहुसंख्यक समुदाय का लोकतंत्र पर विश्वास काफी हद तक कम हो गया है।

इस हक़ीकत को हम भी तसलीम करते हैं कि लोकतंत्र में मतों का महत्व होता है और लोकतंत्र के अधिकांश फायदे भी इन्हीं समुदायों के हिस्से में आते हैं जो बहुसंख्यक होते हैं लेकिन इस हकीक़त को भी माने बगैर चारा नहीं है कि जो बहुमत लोकतंत्र के नाम पर सत्ता के गलियारों तक पहुंच कर देश के भाग्य का मालिक बने है इसकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। देश में कानून व्यवस्था हो समाज खुशहाल हो और तरक्की के रास्ते पर चल रहा हो और अल्पसंख्यक जान-माल की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो इनकी इज्जत आबरू की तरफ कोई आंख उठाकर भी न देख सके और इनमें यह यकीन जिन्दा हो जाये कि इनकी धार्मिक पहचान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और वह अपनी बात बेख़ौफ कह सके। ये सब लोकतंत्र के बुनियादी तकाज़े और लोकतंत्र के नाम पर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली बहुमत के अहम फरायज हैं। क्या हमारा वर्तमान धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र इन तकाजों को पूरा कर रहा है और क्या हमारे क्या हमारा वर्तमान ध र्मनिरपेक्ष लोकतंत्र इन तकाजों को पूरा कर रहा है और क्या हमारे लोकतांत्रिक शासकों को अल्पसंख्यकों के हित में इसे किसी हद तक भी पूरा कर रहे हैं ये ऐसे सवालात है जिनके जवाबात के लिये हमें गत चौहत्तर सालों का जायज़ा लेकर फैसला करना होगा।

गत 74 साल के लोकतांत्रिक सफर का अगर हम इंसाफ के साथ जायज़ा ले तो यह कहना कुछ मुबालगा न होगा कि सेकुलर लोकतंत्र का हमारा नारा हकीक़त नहीं फ्राड है जिसने, आजादी और लोकतंत्र के अर्थ को हो बिगाड़कर रख दिया है। यह कैसी आजादी और लोकतंत्र है जिसके साये में निकलने वाला हर सूरज अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की तबाही की खबर लेकर आता है। साम्प्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर है लोकतंत्र के इन चौहत्तर सालों में दस हजार से अधिक ऐसे भयानक दंगे हो चुके हैं जिन्होंने हजारों हजार औरतों को बेवा और लाखों बच्चों को अनाथ बना डाला है।

2014 के बाद से तो माहौल और बदल गया है। गत चौहत्तर साल के लोकतांत्रिक सफर का अगर हम इंसाफ के साथ जायज़ा ले तो यह कहना कुछ मुबालगा न होगा कि सेकुलर लोकतंत्र का हमारा नारा हकीक़त नहीं फ्राड है जिसने, आजादी और लोकतंत्र के अर्थ को हो बिगाड़कर रख दिया है। यह कैसी आजादी और लोकतंत्र है जिसके साये में निकलने वाला हर सूरज अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की तबाही की खबर लेकर आता है। साम्प्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर है लोकतंत्र के इन चौहत्तर सालों में दस हजार से अधिक ऐसे भयानक दंगे हो चुके हैं जिन्होंने हजारों हजार औरतों को बेवा और लाखों बच्चों को अनाथ बना डाला है। उद्योग धंधों और प्रगति के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिये गये और अगर किसी जगह या शहर के मुसलमान अपनी कोशिश और मेहनत के द्वारा तरक्की के इस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं तो इन्हें इबरतनाक सजा दी जाती है जिसकी तल्खी इनकी आने वाली नस्लें तक महसूस करती रहेगी। मुसलमानों की शिक्षा संस्थाओं और पर्सनल लॉ और उर्दू के साथ हमारी लोकतांत्रिक सरकार का क्या रवैया है इसे बताने की जरूरत नहीं। आजादी के बाद सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को पाकिस्तान का गढ़ कहा जाता था और जिसकी इसे बराबर सजा दी गई। आज मुसलमानों के तमाम छोटे बड़े शिक्षा संस्थान और इनकी धार्मिक शिक्षा संस्थाओं को आई. एस। एस। का गढ़ करार दिया जा रहा है। मुस्लिम पसर्नल लॉ आज भी इतना ही असुरक्षित है जितना गुलामी और ब्रिटिश साम्राज्य के समय में था उर्दू आज भी इसी कसम पुरसी और तआस्सुब का शिकार है जिसका शिकार वह आज़ादी के बाद थी, सरकार की ओर से जारी होने वाली फलाही स्कीमों पर सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय का हक ही समझा जा रहा है। अव्वल तो मुसलमानों तक इनको आवाज ही नहीं पहुंचती और अगर पहुंचती भी है और वह इस दिशा में कुछ कोशिश करते भी हैं तो कदम-कदम पर अफसरशाही उनका रास्ता रोक कर उनको पीछे हटने पर मजबूर करती है। ये और इस तरह की बहुत से हालात हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को इस संदेह में मुक्तला कर दिया है कि हम लोकतंत्र की छाया में जीवन गुजार रहे हैं या कोई तानाशाही हमारा शोषण कर रही है।

अगर हमारे शासकों को वाकई लोकतंत्र प्रिय है और वह सच्चे दिल से चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र फले-फूले 'अपने नारे ''सबका साथ, सबका विश्वास,'' पर सच्चे मन से अमल करना होगा। हमारे लोकतांत्रिक शासक भी अगर न्याय और शांति का दौर वापस लाना चाहते हैं तो इन्हें भी इन्हीं उसूलों को अपनाना होगा जो हमारे संविधान में दिए हैं और अगर वह इसी तरह लोकतंत्र को अपनी इच्छाओं का खिलौना बनाये रहे जैसे वह गत चौहत्तर सालों से बनाये हुये हैं तो हम सफाई के साथ कह देना चाहते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की वह बदतरीन किस्म है जिसकी मौजूदा दौर में कोई गुंजाइश नहीं।

आज जब हम अपने गणतंत्र के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वे अल्पसंख्यकों के हित के लिए भी क़दम उठाए और उनको आगे आने का अवसर दें, तभी हम इस देश को असल गणतंत्र कह सकते हैं।□□

मेरा वतन वही है

चिश्ती ने जिस जमीं पे पैगामे हक सुनाया
नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया
तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया
जिसने हेजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।
सारे जहां को जिसने इल्मो-हुनर दिया था,
यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था
मिट्टी को जिसकी हक़ ने जर का असर दिया था
तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है
टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से
फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से
बदहत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से
मीरे-अरब को आई ठण्डी हवा जहां से

अल्लामा इक़बाल

गणतंत्र दिवस मुबारक मगर...

जिस वक्त ये अख़बार आप के पास पहुंचेगा, पुरा देश लोकतंत्र का 75वाँ महान समारोह मना रहा होगा। 26 जनवरी 1950 में नया संविधान देश में लागू किया गया जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रमुख महत्व देकर हर नागरिक को बिना धर्म सम्प्रदाय का भेदभाव किये कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं जिनमें जिन्दगी की ज़रूरतों के अलावा इस बात की भी ज़मानत दी गई थी कि अब जबकि भारत में सेकुलरिज्म की बुनियाद पर लोकतंत्र का क़याम अमल में आया है। हर व्यक्ति को चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी समाज या धर्म से क्यों न हो। जानमाल इज्ज़त व आबरू व दीन की पूरी तरह रक्षा की जायेगी। हमारे क़ानून साज़ो ने बक़्त के तकाज़ों और देश की धार्मिक व भाषाई स्थिति को देखते हुये संविधान की धारा 25 के द्वारा इस बात को सुनिश्चित कर दिया था कि हर भारतीय चाहे सरकार किसी की भी क्यों न हो इसे किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होगा। आज जबकि हम लोकतंत्र का 75वीं समारोह मना रहे हैं इन कीमती 74 सालों में हमने और हमारी सरकारों ने इस सेकुलर लोकतंत्र की कितनी हिफाज़त की और संविधान में दी गई ज़मानतों पर किस क़दर अमल किया गया, हमें अपना जायज़ा लेना चाहिये और सोचना चाहिये कि जानमाल और इज्ज़त आबरू की सौ साल की कुर्बानियों के बाद होने वाली आजादी के परिणाम में मिलने वाले लोकतंत्र की सुरक्षा के लिये हमने क्या कुछ किया है।

आज़ादी से पहले कहा जाता था कि देश में आर्थिक बदहाली, साम्प्रदायिक घृणा और नागरिकों के दीन धर्म में हस्तक्षेप अंग्रेजी साम्राज्य की देन है और वह ये सब बातें अपनी सत्ता के दिन बढ़ाने के लिये कर रहे थे, मगर अब जबकि खुद अपनी लोकतांत्रिक सरकार है तो ये सब बातें आखिर क्यों हो रही है। आज लोकतंत्र पर 74 साल गुजर जाने के बाद भी अगर देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक बदहाली और मुद्रास्फीति का शिकार है। आज अगर देश की आबादी गरीबी की सतह से नीचे जिन्दगी गुजारने पर मजबूर है। आंज यहां अगर अल्पसंख्यक ख़ासकर मुसलमान जो इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरयत है मौत व जिन्दगी की कशमकश से झूझ रही है और अगर आज इनको यह शिकवा है कि इनका दीन व ईमान खुद सरकार के द्वारा पामाल किया जा रहा है और अगर वह यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक दंगों के द्वारा इनकी सुनियोजित नस्लकुशी की जा रही है तो क्या हमारे देश की लोकतात्रिक व्यवस्था के लिये यह चिन्ता का विषय नही हैं क्या? भारत के लोकतांत्रिक संविधान ने देश के हर नागरिक विशेषकर अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया था कि इनके पर्सनल लॉ और धार्मिक पहचान की हर कीमत पर रक्षा की जायेगी मगर इस लोकतांत्रिक संविधान के लागू होने के बाद शायद ही कोई एक साल भी ऐसा न गुजुरा होगा जब सुनियोजित तरीके पर मुसलमानों की पहचान इनकी मजहबी परम्परायें और इनके पर्सनल लॉ और उनके इबादतगाहों पर सुनियोजित तरीकों से हमला करने की कोशिश न की गई हो, समान नागरिक संहिता का हव्वा खड़ा करके मुसलमानों को बराबर परेशान और उत्तेजित किया जा रहा है। यह यही स्थिति है जिसने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर दिया है।

आज़ादी से पहले कहा जाता था कि देश में आर्थिक बदहाली, साम्प्रदायिक घृणा और नागरिकों के दीन धर्म में हस्तक्षेप अंग्रेजी साम्राज्य की देन है और वह ये सब बातें अपनी सत्ता के दिन बढ़ाने के लिये कर रहे थे, मगर अब जबकि खुद अपनी लोकतांत्रिक सरकार है तो ये सब बातें आखिर क्यों हो रही है। आज लोकतंत्र पर 74 साल गुजर जाने के बाद भी अगर देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक बदहाली और मुद्रास्फीति का शिकार है। आज अगर देश की आबादी गरीबी की सतह से नीचे जिन्दगी गुजारने पर मजबूर है।

हिन्दुस्तान में मुसलमानों और इनके संगठनों की इच्छा है कि वे लोकतांत्रिक और आजाद भारत में अपनी उचित भूमिका निभायें और इसके विकास व निर्माण में अपना वह हक अदा करें जो देश की मुहब्बत ने इनको विया है। यह किस कदर अफसोस की बात है कि मुसलमानों को नित नये सुनियोजित तरीकों से इनके इस वाजिब किरदार की अदायगी से रोकने की बराबर कोशिशें की जा रही हैं।

मुसलमानों के नजदीक सबसे अहम मसला इनकी शरीअत और इनके दीन ईमान की सुरक्षा है परन्तु गत 74 सालों में जिस तरह इनकी शरीअत और इनके ईन ईमान के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है, गत (2014) दस सालों में इसमें तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई है, इसने लोकतंत्र पर इनके विश्वास को कमजोर कर दिया है। वह ये सोचने पर मजबूर किये जा रहे है कि लोकतंत्र में इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और यह साम्प्रदायिक तत्वों की एक ऐसी साजिश है। जिसका सौधा नुकसान देश की एकता व अखंडता पर पड़ सकता है।

जहां तक दूसरी अल्पसंख्यक समस्याओं और मामलात का सम्बन्ध है तो एक लोकतांत्रिक संविधान के बावजूद अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को इनकी समस्याओं और मामलात में बराबर नजरअंदाज़ किया जा रहा है। आज डिग्रियां और सनदें लिये न जाने कितने अल्पसंख्यक लोग और मुसलमान बरबदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इनके साथ काबिलियत के बावजूद नौकरियों में दूसरे दर्जे के नागरिक बाला रवैया इख्तयार किया जाता है। देश की व्यवस्था और रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में इनको इनके हिस्से से वचित कर दिया जाता हैं जो इनके जीवन पर खराब असर डाल रहा है और इनके दिलों में शक शुब्हा के साथ-साथ यह सवाल भी पैदा कर रहा है कि क्या लोकतंत्र के फायदों पर सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग की ही हक़ है? और अगर ऐसा ही है ये साफ-साफ लोकतान्त्रिक संविधान की खुली ख़िलाफार्ज़ी है।

लोकतंत्र की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति या जमाअत का ही अधिकार नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी देश के हर नागरिक पर है और यह हिफाजत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हर हिन्दुस्तानी नागरिक को इसके मौलिक अधिकार प्रदान न कर दिये जाये यही लोकतंत्र की आत्मा और भारतीय संविधान से वफादारी है। इसलिये आईये हम लोकतंत्र की इस 74वीं सालगिरह पर हम एक बार फिर यह अहद करें कि हम देश में लोकतंत्र की बुनियादों को मज़बूत करेंगे और भारतीय संविधान ने हर भारतीय नागरिक को जो अधिकार दिये हैं इनका जायज़ और सही इस्तेमाल करके देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ायेंगे।

हम आशा करते हैं कि हमारे वर्तमान शासक अल्पसंख्यकों ख़ासकर मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकारों का पालन करने में सहायक की भूमिका अदा करेंगे, हम समस्त पाठकों को इस महान गणतंत्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। ❑❑

जमहूरियत पर अशआर

जमहूरियत इक तर्जे हुकूमत है कि जिसमें
बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते
——— अल्लामा इकबाल

जमहूरियत के बीच फंसी अकल्लियत था दिल
मौक़ा जिसे जिधर से मिला वार कर दिया
——— नोमान शौक

यही जमहूरीयत का नुक़्स है जो तख़्त-ए-शाह पर
कभी मक्कार बैठे हैं कभी गद्दार बैठे हैं
——— डाक्टर आजम

झुकाना सीखना पड़ता है सर लोगों के क़दमों में
यूँही जमहूरियत में हाथ नहीं आती
——— महेश जानिब

सुनने में आ रहे हैं मुसर्रत के वाक़िआत
जमहूरियत का हुस्न नुमायां है आजकल
——— शेअरी भोपाली

नाम उसका आमरियत हो कि हो जमहूरियत
मुंसलिक फिरऔनीयत मस्नद से तब थी अब भी है
——— मुर्तजा बिरलास

जमहूरियत भी तरफा तमाशा का किस क़दर
लौह-ओ-कलम की जान यद अहरमन में है
——— बेबाक भोजपोरी

ख़ास ख़बरें

दूसरी बार यू.एस. ब्रिटेन का निशाना बने हुती

अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने सोमवार रात को यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के 8 जगहों में मौजूद कई ठिकानों पर बमबारी की। दूसरी बार सहयोगी देशों ने यह कार्रवाई की। हमले में हूती के मिसाइल भंडार स्थलों, ड्रोन और लॉन्चर को नष्ट किया गया। इसके लिए युद्धपोत और पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल तोमाहॉक और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया।

भारत के हितों पर पड़ता है इजराइल- हमास संघर्ष का सीधा असर : भारत

भारत के एक शीर्ष राजनयिक ने संयुक्त वं राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्यों को बताया कि पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष से हिंद महासागर में समुद्री वाणिज्यिक यातायात सुरक्षा प्रभावित हो रही है और इसका सीधा असर देश के ऊर्जा एवं आर्थिक हितों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थाई प्रतिनिधि आर. रवींद्र ने यूएनएससी में खुली चर्चा के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा, 'पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से हिंद महासागर में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है जिसमें भारत से जुड़े जहाजों पर कुछ हमले भी शामिल हैं।' उनकी यह टिप्पणी लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों में वृद्धि के बीच आई है। रवींद्र ने हूती विद्रोहियों का नाम लिए बगैर कहा, 'यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत चिंता साइन बनाम का विषय है और इसका भारत के ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। यह भयावह स्थिति किसी भी पक्ष को लाभ नहीं पहुंचाएगी और इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए।' क्षेत्र में समुद्री यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंताएं रही हैं।

अमरीका ने मिलिशिया के ठिकानों पर किए हमले

वाशिंगटन : अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उनकी सेना ने पिछले कुछ दिनों में इराक और सीरिया में अमरीकी सैनिकों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के प्रतिशोध में इराक़ में ईरान समर्थित एक मिलिशिया के तीन ठिकानों पर हमले किए। 'यूएस सेंट्रल कमांडर ने बताया कि अमरीका ने सीरियाई सीमा के समीप पश्चिमी इराक़ में मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए। ऑस्टिन ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमरीकी सैन्य बलों ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह कतैब हिजबुल्ला और अन्य ईरान समर्थित समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तीन ठिकानों पर आवश्यक हमले किए।

इस्लामियात

आजिज़ी व इनकेसारी वाले मोमिनों को बशारत है

मोमिनों के लिये सबसे अहम फरीज़ा पांच वक़्तों की नमाज़ है, इसमें अल्लाह की रिज़ा भी हासिल होती है, दीन व दुनिया में हर तरह की सफलता की ज़मानत है। पवित्र कुरआन में कई जगहों पर नमाज़ की फर्ज़ियत और फज़ीलत को बयान किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी आंखें की ठण्ठक नमाज़ में है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने नमाज़ को आंखों की ठंडक कहा है तो उनकी उम्मत को भी नमाज़ की आंखों की ठंडक बनाना चाहिए और इसकी पाबंदी को अपने ऊपर लाज़िम (अनिवार्य) करना चाहिए। मर्दों के लिये मस्जिद में आकर जमाअत से नमाज़ अदा करने को वाजिब फरमाया गया है और जो जमाअत से नमाज़ को लगातार छोड़ता हो और नमाज़ की पाबंदी और अदायगी में ग़फ़लत करता हो वह फासिक़ हो जाता है। नमाज़ी महबूब होता है बेनमाज़ी रांद-ए-दरगाह हो जाता है। सात साल की आयु से ही बच्चों को नमाज़ की आदत डालनी चाहिए।

कुरआन करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया : अर्थ

आलिफ लाम-मीम, यह अज़ीमुश्शान किताब है, इस में किसी शक व शुब्हा की गुंजाइश नहीं है यह सर-चश-म-ए हिदायत है, मुत्तक़ियों के लिये जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं और नमाज़ को क़ायम करते हैं और हमने उन्हें जो माल व असबाब दिया है, ख़र्च करते हैं और वह लोग जो ईमान लाते हैं उन पर जो ऐ महबूब तुम्हारी तरफ उतारी गई है और जो तुम से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर उतारा गया और आख़िरत पर यकीन रखते हैं यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं (सूरे बक़रा)

यक़ीनन कुरआन करीम अल्लाह का पवित्र कलाम (वाणी) है जो शत प्रतिशत सत्य है इसमें किसी भी प्रकार का कण बराबर भी शक व शुब्हा की गुंजाइश नही है इस में आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पहले के नबियों के हालात भी हैं और उन लोगों का भी उल्लेख है जिन पर अल्लाह तआला का इन्आम हुआ और उन बदनसीबों का भी ज़िक्र है जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। इसमें कुदरत की निशानियों का बहुत तफसील से बयान है और आधुनिक साइंस के ऐसे-ऐसे हक़ायक़ बयान किये गये हैं कि माहिर साइंसदां भी आश्चर्यचकित हैं और पवित्र कुरआन की हक्क़ानियत (सहीह होने के) मोतरिफ नज़र आते हैं। इस में नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शाने महबूबियत और अज़मत व रिफअत (महानता) का विस्तृत बयान है कि नबी के लिये हर मोमिन का क्या अक़ीदा होना चाहिए उनका अदब व सम्मान किस शान से होना चाहिए उनकी ताज़ीम व तौकीर का क्या तरीक़ा होना चाहिए इसका भी तफसील के साथ ज़िक्र है। पवित्र कुरआन की तिलावत का भी बहुत ज़्यादा सवाब है बिला वज़ू कुरआन को हाथ में लेना मना है। कुरआन करीम को देखकर पढ़ना अफ़ज़ल है चूंकि इसमें तिलावत भी है और कुरआन करीम के शब्दों का दीदार भी हो जाता है। हर तिलावत करने वाला ''ला रैबा फीह'' का इक़रार करता हुआ नज़र आता है।

यह सर-चश-म-ए हिदायत (मार्ग दर्शन का स्रोत) है मुत्तक़ियों के लिये जिनके दिल में ईमान है और अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करने का जज़्बा भी है उन्हें हर वक़्त सत्य मार्ग की तलाश है वह लोग अल्लाह से हर वक़्त डरते हैं और उसकी रहमत के तलबगार होते हैं वह निडर होकर ज़िन्दगी नहीं गुज़ारते बल्कि उनके दिल अल्लाह के जलाल और उसके अज़ाब के डर से लरज़ते रहते हैं उन्हें अपनी इबादतों पर घमंड नहीं होता। वह भय और उम्मीद के बीच ज़िन्दगी गुज़ारते हैं उन्हें अल्लाह का डर भी है और उस की रहमतों पर भरोसा भी है उन्हें उम्मीद रहती है कि यक़ीनन वह रहीम व करीम उनकी मग़्फ़िरत करेगा और उनके लिये अल्लाह के महबूब सिफारिश फरमाएंगे। उन्होंने अल्लाह तआला को अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा नहीं लेकिन उनका ईमान बहुत मज़बूत है उन्हें अल्लाह के वजूद के बारे में ज़रा सा भी शक नहीं है, वह हर वक़्त यक़ीन रखते हैं कि अल्लाह तआला उन्हें हर हाल में देख रहा है और वह हर लम्हा अपनी ज़िन्दगी को इस परवरदिगार की मर्ज़ी के मुताबिक़ गुज़ारने के लिये कोशां (प्रयासरत) रहते हैं, वह लोग जो कुरआन की तिलावत करके उसके अनुवाद और व्याख्या का भी अध्ययन करते हैं वह नबी के आशिक़ हैं और उनकी पवित्र सीरत और सुन्नतों पर अमल करने को अपनी ज़िन्दगी की पूंजी समझते हैं ऐसे ही लोग मुत्तक़ी कहलाने का हक़ रखते हैं ऐसे ही लोग कामयाब होते है, दुनिया भी उनके क़दम चूमती है और आख़िरत में भी अल्लाह की रहमत से मालामाल होंगे।

हर काम को करने से पहले सीखना पड़ता है, कोई भी काम मेहनत के बग़ैर नहीं किया जा सकता। इस्लाम दीन अल्लाह का प्रिय मज़हब है जिस की दावत व प्रचार के लिये अंबिया-ए-किराम अलैहुमुस्सलाम तशरीफ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन्नबी (सब नबियों में आख़िरी नबी) हैं। इन्सान के आदेशों से जुड़ा होना चाहिए। हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, बोलना और सोचना सब कुछ शरीअत के अनुसार होना चाहिए, तब ही हम आख़िरत में कामयाब हो सकते हैं इसलिये दीन को सीखने के लिये अल्लाह के औलिया की संगत अपनाने की ज़रूरत है और किताबों का बराबर अध्ययन करते रहना चाहिए।

सूरे हज में अल्लाह तआला ने फरमाया। अर्थ :

''और आजिज़ी व इन्केसारी (विनम्रता) करने वालों के लिये खुशख़बरी और बशारत है कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं और वह अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहते हुए हर दुख पर सब्र करते हैं और नमाज़ को क़ाइम रखने वाले हैं और जो माल व दौलत उन्हें दिया है उस में से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं।''

अल्लाह तआला को आजिज़ी और इन्केसारी पसंद है। घमंड और गुरूर इन्सान के कर्मों को बर्बाद कर देता है जैसे एक मुलज़िम अदालत में पेश होता है जैसे गुलाम अपने आक़ा के सामने पेश होता है, इस से भी कहीं ज़्यादा आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने पेश होना चाहिए। बन्दा हर वक़्त हर जगह अल्लाह के सामने है तो फिर हर वक़्त उसे गुनाहों से बचते रहना चाहिए। अल्लाह ने रुपया, पैसा दिया है उसे ऐसी ही जगह ख़र्च करना चाहिए जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो। ग़रीबों, ज़रूरतमंदों की इम्दाद में, बेवा और यतीम (अनाथ) लोगों की मदद में, नेक कामों में जिनका पैसा लगता है वह आख़िरत में कामयाब और निजात का सबब बनता है लेकिन जो पैसा नाजायज़ तौर पर ख़र्च होता है, रियाकारी (दिखावा) फिजूलख़र्ची और अनर्थ कामों में ख़र्च होता है वह जान का वबाल बनेगा आख़िरत में एक-एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में ऐश व इशरत, ठाट बाट की ज़िन्दगी आख़िरत में पकड़ का सबब होगी।

हदीस शरीफ़ में औलाद की तरबियत की बहुत अहमियत है फरमाया गया कि सदक़ा करने से बेहतर है कि यह रुपया औलाद को तालीम, तहज़ीब व तरबियत में लाया जाए और उन्हें शरीअत और दीन का दाई (प्रचारक) बनाया जाए। छोटे बच्चे अपने मां-बाप और रिश्तेदारों को जो कुछ करता देखते हैं वहीं बातें उनके ज़हन पर नक़्श हो जाती हैं इसलिए उनकी तरबियत के लिए भी ज़रूरी है कि मां-बाप ख़ुद को शरीअत के अहकाम के मुताबिक़ ढालें और नेक काम करें ताकि औलाद जिंदगीभर इन पर कायम रहे ताकि उनके लिए सद-क़-ए-जारिआ हो।

पैसा कमाने का तरीक़ा भी जायज़ होना चाहिए, हलाल कमाई के असरात अच्छे होते हैं इनसे ईमान रोशन होता है, इबादत में दिल लगता है, शरीअत की पाबंदी का जज़्बा जागरुक होता है। ख़ुद-ब-ख़ुद गुनाह से क़दम रुक जाते हैं अगर कोई गुनाह सरजद भी हो जाए तो दिल भी डर जाता है और तौबा की तौफ़ीक़ हो जाती है लेकिन रोज़गार कमाने में जो नाजायज़ बातों को अपनाते हैं सूद का कारोबार करते हैं वह ज़ाहिर में बहुत मालदार और खुशख़ुर्रम नज़र आते हैं लेकिन उन पर अल्लाह का गज़ब (नाराज़गी) नाज़िल हो कर रहती है। परवरदिगार उन्हें तौबा की मोहल्लत ज़रूरत देता है लेकिन हिसाब-किताब से वो ग़ाफ़िल रहते हैं इसलिए नाजायज़ कारोबार हरगिज़ नहीं करना चाहिए और तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह तआला को आजिज़ी व इन्कसारी, तवाज़ो और कस्र नफसी, खुशूअ् ख़ुज़ूअ् पसंद है यह हर मोमिन का शेवा होना चाहिए।

गुलामाने नबी की शान का फीरोज़ क्या कहना

बज़ाहिर ख़ाक पर बैठे हैं इज़्ज़त और ही कुछ है। ❑❑

अल्लाह तआला को आजिज़ी और इन्केसारी पसंद है। घमंड और गुरूर इन्सान के कर्मों को बर्बाद कर देता है जैसे एक मुलज़िम अदालत में पेश होता है जैसे गुलाम अपने आक़ा के सामने पेश होता है, इस से भी कहीं ज़्यादा आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने पेश होना चाहिए। बन्दा हर वक़्त हर जगह अल्लाह के सामने है तो फिर हर वक़्त उसे गुनाहों से बचते रहना चाहिए। अल्लाह ने रुपया, पैसा दिया है उसे ऐसी ही जगह ख़र्च करना चाहिए जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो।

नूर-ए-क़ुरआन

सूरा बकरह नं। 02

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

उन लोगों का उदाहरण जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ऐसा है कि जैसे एक दाना जिससे सात बालें उगें हर बाल में सौ सौ दाने हों और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ाता है और अल्लाह असीम क्षमाशील सब कुछ जानने वाला है।

अर्थात् अल्लाह के मार्ग में थोड़े माल के खर्च करने का भी सवाब बहुत है जैसे एक दाने से सात सौ दाने पैदा हो जाये और अल्लाह चाहे तो किसी के लिए इससे भी अधिक कर दे। जैसे सात सौ से सात हजार और इससे भी अधिक कर दे और अल्लाह बहुत बख़्शिश करने वाला है वह प्रत्येक खर्च करने वाले की नीयत और उसके खर्च की संख्या जऔर माल की दशा को भली-भाँति जानता है अर्थात् प्रत्येक से उसके आधार पर बर्ताव करता है।

जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर ख़र्च करने के पश्चात् न अहसान रखते हैं और न सताते हैं उनके ही लिए अपने रब के यहां उनका सवाब (पुण्य) है और न उन पर कोई डर होगा और न उनको ग़म होगा।

जो लोग जल्लाह की राह में खर्च करते हैं और ख़र्च किये पर न ज़बान से अहसान रखते हैं और न सताते हैं न ताना करते हैं और न सेवा लेते हैं और न अपमान करते हैं उन्हीं के लिए पूर्ण सवाब है और न उनको सवाब कम होने का डर है और न सवाब के नुकसान से शोकाकुल होंगे।

नर्म बात कह देना और क्षमा करना उस दान से अच्छा है जिसके पीछे सताना हो और अल्लाह वे परवाह है बड़ा सहनशील है।

अर्थात् मांगने वाले को नर्मी से उत्तर देना और उसके बार-बार मांगने और बुरी आदत को क्षमा करना अच्छा है। उस दान से जिस पर बार-बार लज्जित करें या अहसान रखे। अल्लाह स्वयं वे परवाह है उसको किसी के माल की आवश्यकता नहीं। जो कोई उसके रास्ते में दान करता है अपने लिए करता है। वह सहनशील है सताने पर दण्ड देने में शीघ्रता नहीं करता।

ऐ ईमान वालो अहसान रखकर और कष्ट पहुंचाकर अपने दान को न खो डालो, उस व्यक्ति की भांति जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता है।

अर्थात् दान के देने के पश्चात् असहाय को सताने और अहसान रखने से दान का पुण्य जाता रहता है या दूसरों को दिखाकर, इसलिए छान करना कि लोग दानी समझें। इस प्रकार के दान का पुण्य भी कुछ नहीं होता। रहा यह कहना कि वह अल्लाह और क़यामत के दिन पर विश्वास नहीं रखता। यह दान को नष्ट करने के लिए शर्त नहीं है क्योंकि दान तो केवल दिखावे से ही खोया जाता है। यद्यपि खर्च करने वाला ईमान ही क्यों न रखता हो। परन्तु इसको इसलिए बढ़ाया है कि यह ज्ञान हो जाये कि दिखावा ईमान वाले के योग्य नहीं बल्कि यह तो कपटाचारियों का स्वभाव होता है।

तमिलनाडु | पोंगल के साथ गर्माने लगी सियासत

तमिलनाडु में इन दिनों पोंगल का उल्लास है। यह तमिल पंचांग के अनुसार, तमिल नववर्ष में थाई मास की शुरुआत है। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों ने भी राज्य में अपनी रणनीतियों को फिर आज़माने की कोशिश शुरू कर दी है। तमिल पंचांग में थाई महीना बहुत शुभ माना जाता है, और इस महीने में तमाम तरह की गतिविधियों को गति मिल जाती है, क्योंकि इसका पिछला महीना मार्गजी अशुभ माना जाता है, जिसमें कोई नया काम नहीं होता। चूंकि यह एक फसली उत्सव है, इसलिए इसे गांवों में धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु के लगभग सारे बड़े शहर खाली-से हो जाते है, क्योंकि बहुत लोग गांव चले जाते हैं। जो लोग शहर में बचते हैं, वे भी ग्रामीण संस्कृति के रंग-ढंग में डूबे मिलते हैं।

अब तो सियासी पार्टियां, सार्वजनिक इकाइयां और निजी कंपनियां भी पारंपरिक पोंगल उत्सव का आयोजन करने लगी है। जगह-जगह रंग-बिरंगी रंगोली तैयार की जाती है। एक ग्रामीण खेल विशेष रूप से होता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं आंखों पर पट्टी बांधकर मिठाइयों से भरे मिट्टी के बर्तन तोड़ते हैं। इस अवसर पर तमिल लोग अपनी भाषा, समृद्ध और प्राचीन संस्कृति को भी याद करते हैं, जो उनकी पहचान का आधार बनती है। तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। यह ईसा पूर्व तीसरी सदी से लगातार बोली जा रही है। यह संस्कृत से भी पुरानी भाषा मानी जाती है और इसका मूल द्रविड़ है। इसने अपने अधिकांश मूल तत्वों को अभी भी संजोए रखा है। यही कारण है, तमिल अपनी भाषा पर दृढ़ता से क़ायम रहते हैं।

यही कारण है कि कुछ साल पहले तमिलों ने अपनी राजनीतिक मान्यताओं से हटकर पारंपरिक ग्रामीण खेल जल्लीकट्टू को फिर बहाल करने के लिए हाथ मिला लिया था। कई अधिकार समूहों ने पशुओं के प्रति क्रूरता का आरोप लगाते हुए जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध की मांग की थी। इस खेल में देशी बैलों को क़ाबू में करने की कोशिश करते हुए अनेक युवा घायल हो जाते थे और कुछ की मौत हो जाती थी। इसके बावजूद लोगों और उनकी पुरानी परंपरा की ही जीत हुई। वैसे, दोनों राष्ट्रीय दलों को लोगों की परंपरा को समझने में कुछ समय लगा। पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा भी मान गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने तमिलों को लुभाने के लिए इस खेल संस्कृति को अपनाने का फैसला किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री पारंपरिक वस्त्र वेष्टि पहनकर त्योहार मनाने के लिए रविवार को दिल्ली में अपने कैबिनेट सहयोगी एल मुरुगन के सरकारी आवास पर पहुंच गए।

पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की चेन्नई यात्रा तमिलों को यह बताने के लिए थी कि प्रधानमंत्री को उनके हित की परवाह है। ध्यान रहे, बाढ़ का सामना करने वाले तमिलनाडु को राहत राशि देने में केंद्र सरकार की देरी की कड़ी आलोचना हुई है। हालांकि, भाजपा के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, पर अब तक उन्हें सीमित कामयाबी ही हासिल हुई है।

अन्नाद्रमुक के एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने के फैसले से राज्य में सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को ही हुआ है। चुनाव बिल्कुल करीब है, पर भाजपा को अभी भी अन्नाद्रमुक से समझौते की उम्मीद है। दूसरी ओर, भाजपा के साथ फिर गठबंधन के लिए अन्नाद्रमुक में शायद ही कोई दिलचस्पी है। अन्नाद्रमुक राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए अल्पसंख्यक -मुस्लिम और ईसाई समर्थन पर नजर रखती है।

अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ तमिलनाडु में तीसरा मोर्चा बनाने के भाजपा के प्रयासों को कम ही कामयाबी मिली है। दूसरी ओर, अन्नाद्रमुक को एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाने में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो द्रमुक के नेतृत्व वाले दुर्जेय गठबंधन का मुक़ाबला कर सके।

भाजपा के आला नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि वे अन्नाद्रमुक से अलग हुए गुटों पर निगाह गड़ाए हुए हैं। एक, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम का गुट है। और दूसरा, एन शशिकला के भतीजे टीटीके दिनाकरन के नेतृत्व वाला गुट है, जिनके साथ गठबंधन करने का फैसला भाजपा ने लिया है। दिवंगत नेता-अभिनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकती है। वैसे अभी भी भाजपा का लक्ष्य ए पलानीसामी (ईपीएस) के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करना है, जो पिछले वर्ष एनडीए से बाहर हो गई है। वैसे भाजपा ने हार नहीं मानी है और अभी भी गठबंधन की कोशिशों में लगी है।

राज्य की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी पीएमके भाजपा गठबंधन में शामिल हो सकता है। पहले भी इस पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। यह देखने वाली बात है कि पीएमके और जीके वासन की टीएमसी या तमिल मनीला कांग्रेस किसके साथ जाएगी, अन्नाद्रमुक के साथ या भाजपा के साथ ? वैसे, गठबंधन बनाने में भाजपा ही नहीं, अन्नाद्रमुक को भी परेशानी हो रही

बाक़ी पेज 11 पर

ग़रीबी के दलदल में और पांच अरब लोग

दुनिया के पांच सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से '1.4 करोड़ अमेरिकी डालर प्रति घंटे की दर से' 405 अरब अमेरिकी डालर से दोगुनी से अधिक बढ़कर 869 अरब अमेरिकी डालर हो गई है, जबकि 'विभाजन के इस दशक' में करीब पांच अरब लोग पहले ही गरीब हो चुके हैं। गैर सरकारी संगठन आक्सफैम ने सोमवार को 'असमानता और वैश्विक कार्पोरेट शक्ति' पर जारी रपट में तथ्य सामने रखा। वहीं, रपट में कहा गया है 1ध कि विश्व को एक दशक में अपना पहला खरबपति मिल सकता है जबकि ग़रीबी ख़त्म करने में दो शताब्दियों से अधिक समय लगेगा। आक्सफैम ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) की वार्षिक बैठक के पहले दिन सोमवार को अपनी वार्षिक असमानता रपट जारी करते हुए कहा कि दुनिया के 10 सबसे बड़े निगमों में से सात में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या प्रमुख शेयरध ारक एक अरबपति हैं। रपट में कहा गया कि 148 शीर्ष निगमों ने 1,800 अरब अमेरिकी डालर का मुनाफा कमाया, जो तीन साल के औसत से 52 फीसद अधिक है। अमीर शेयरध ारकों को भारी भुगतान किया गया, जबकि करोड़ों लोगों को वास्तविक अवधि के वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा।

आक्सफैम की रपट में कहा गया कि दुनिया के पांच सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से '1.4 करोड़ अमेरिकी डालर प्रति घंटे की दर से 405 अरब अमेरिकी डालर से दोगुनी से अधिक बढ़कर 869 अरब अमेरिकी डालर हो गई है, जबकि 'विभाजन के इस दशक' में करीब पांच अरब लोग पहले ही गरीब हो चुके हैं। आक्सफैम ने सार्वजनिक कार्रवाई के एक नए युग का आन किया, जिसमें सार्वजनिक सेवाएं, कार्पोरेट विनियमन, एकाधिकार को तोड़ना और स्थायी धन और अतिरिक्त लाभ करों को लागू करना शामिल है। रपट में कहा गया, 'अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो एक दशक के भीतर दुनिया को पहला खरबपति मिल जाएगा, लेकिन गरीबी 229 वर्षों तक खत्म नहीं होगी।' आक्सफैम इंटरनेशनल के अंतरिम कार्यकारी निदेशक अमिताभ बेहार ने कहा कि असमानता की यह स्थिति कोई दुर्घटनावश उत्पन्न नहीं हुई है।

अरबपति वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि निगम बाकी सभी की कीमत पर उन्हें अधिक संपत्ति प्रदान करें। आक्सफैम के अनुसार वैश्विक आबादी का सिर्फ 21 फीसद प्रतिनिधित्व करने के बावजूद 'ग्लोबल नार्थ' के अमीर देशों के पास 69 फीसद वैश्विक संपत्ति है और दुनिया के 74 फीसद अरबपतियों की संपत्ति यहीं है।❑❑

आबादी के पास अब भी घर नहीं, टायलेट सुविधा से 31 प्रतिशत लोग वंचित

देश में 9 साल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अब 11.28% लोग गरीब हैं। ये आंकड़े पिछले दिनों नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) में सामने आए हैं। हालांकि, हालात अब भी बेहतर नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 41.3% लोग बेघर हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद 31% टायलेट सुविधा से वंचित हैं। तमाम अभियानों के बाद भी 44% के पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं हैं। वे लकड़ी-उपलों पर खाना बना रहे हैं। 20 साल में 14.61% लोगों को ही घर मिला है। रिपोर्ट 12 मानकों के आधार पर तैयार हुई है। विश्व बैंक ने दिन में 180 रु। से कम कमाने वालों को ग़रीबी रेखा से नीचे माना है। 2017 में 18.73% आबादी गरीब थी, जो 2021 में 11,90% रह गई। बिहार में सबसे ज़्यादा 26.59 फीसदी ग़रीब बिहार में 26.59% आबादी ग़रीब है। इसके बाद झारखंड (23.34%), यूपी (17.40%), मप्र (15.01%), छत्तीसगढ़ (11.71%), राजस्थान (10.77%) है। केरल (0.48%) में सबसे कम ग़रीबी है। इसके बाद तमिलनाडु (1.48%), तेलंगाना (3.76%), हिमाचल (1.88%) हैं।

किस मानक में कितना सुधारद (मानक : 2019-21 2004-05)

पोषाहार से वंचितः	31.52%	57.47%	शिशु मृत्युदरद :	2.06%	4.84%
खराब मातृ सेहत :	19.17%	33.0%	स्कूल में अनुपस्थितिः	5.27%	21.27%
टॉयलेट से वंचित :	30.93%	70.92%	पेयजल से वंचित :	7.32%	21.34%
बिजली नहीं :	3.27%	32.95%	बैंक खाते नहीं :	3.69%	58.11%
रसोई गैस नहीं :	43.90%	74.40%			

विस अध्यक्ष के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट

जून 2022 में विभाजन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट को 'वास्तविक राजनीतिक दल' घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। विधानसभाध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया था। अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंद्वी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था। इस फैसले ने मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की स्थिति को और मजबूत कर दिया। शिंदे ने 18 महीने पहले ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। गर्मियों में लोकसभा चुनाव और 2024 की दूसरी छमाही में होने वाले राज्य विध ानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में इस फैसले से उनकी राजनीतिक ताक़त बढ़ गई है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार समूह) भी शामिल हैं। नार्वेकर ने कहा था कि कोई भी पार्टी नेतृत्व किसी पार्टी के भीतर असंतोष या अनुशासनहीनता को दबाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई, तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था। निर्वाचन आयोग ने 2023 की शुरुआत में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 'शिवसेना' नाम और 'तीर-धनुष' चुनाव चिह्न दिया था। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और प्रतिद्वंद्वी ठाकरे गुट द्वारा एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपने आदेश में नार्वेकर ने कहा था कि शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु 21 जून 2022 (जब पार्टी विभाजित हुई) से सचेतक नहीं रहे और शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले अधिकृत सचेतक बने । नार्वेकर ने कहा था, 'विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा रहा है।'

खेल जगत

ओलंपिक में क्या पूरी होगी ज़्यादा पदकों की आस

नए साल 2024 में होने वाले ओलंपिक में भारत की संभावनाओं से पहले बीते साल की सफलताओं पर नजर डालें तो भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 31 रजत व 51 कांस्य पदक के साथ पहली बार पदकों का आंकड़ा सौ पार ले जाते हुए कुल 107 पदक भारत की झोली में डाले। इन्हीं खेलों में एक नया इतिहास बनाने में हमारे पैरा खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने तो हमारे सामान्य खिलाड़ियों को भी पदकों में पछाड़ कर 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदकों की माला देश को पहना कर नया इतिहास ही बना दिया। इस साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 भगस्त तक हो रहे खेलों के महाकुंभ ओलिंपिक की। इसमें दुनिया के 200 से ज्यादा देश भाग लेते हैं। यह आयोजन चार साल में एक बार होता है। पूरी दुनिया के बेहतर से बेहतर खिलाड़ी इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भारत के खेल प्रेमियों की भी तमन्ना है कि उसके खिलाड़ी भी इस महाकुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेकर लौटें। अभी तक के ओलंपिक के 128 साल के सफर में और आज़ादी के बाद के 75 साल में हमारे पास ओलंपिक में ज्यादा उपलब्धियां नहीं है। पिछले ओलंपिक तक भारत के नाम केवल 10 स्वर्ण, 9 रजत व 16 कांस्य सहित कुल 35 पदकों का मामूली खजाना है जो पदक तालिका में प्रथम पांच में रहने वाले देशों के खाते में एक ओलिंपिक में होते हैं।

जिस तरह का भारत का प्रदर्शन अभी तक के ओलंपिक में रहा है, उसे देखते हुए हमारे खिलाड़ी पदकों की संख्या को 10 तक भी पहुंचा देते हैं तो हमारे खेल संघ, खेल मंत्रालय व खेल प्रेमी बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि दहाई के इस आंकड़े के लिए ऐसे 10 दावेदार सौ फीसद नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस महाकुंभ में बेहतरीन खिलाड़ियों का एक बड़ा दल ज्यादा से ज्यादा पदक देश की झोली में डालने का विश्वास दिलाएगा। लेकिन जिन खेलों व खिलाड़ियों पर विश्वास मजबूत दिखाई दे रहा है उनमें सबसे पहला नाम भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का है। इनसे सभी को उम्मीद है कि यह एकबार फिर से सबसे लंबा भाला फेंककर के देश को लगातार दूसरा स्वर्ण पदक दिलाएंगे। इसकी वजह भी मजबूत है क्योंकि अभी दुनिया में अपने खेल में वे सिरमौर हैं। विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता, दोहा व लुसान डायमंड लीग के साथ अन्य प्रतियोगिताओं के ख़िताब नीरज के नाम हैं। ओलंपिक में अन्य खेलों में अगर पदक की आस कर सकते हैं तो वे हैं-निशानेबाज़ी, कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाज़ी, भारोत्तोलन, टेनिस व पुरुष हाकी। इसका कारण भी साफ है कि इन्हीं खेलों में अभी तक ओलंपिक में भारत को पदक मिले हैं।

बैडमिंटन में सात्विक व चिराग लगातार सफलता पा रहे हैं। दोनों ने विश्व टूर के तीन खिताब, एशियाई खेलों व एशियाई चौंपियनशिप का खिताब पिछले साल जीता है। पूरी उम्मीद है कि यह जोड़ी भी बिना पदक के वापसी नहीं करेगी। इन्हीं की तरह महिलाओं में अश्वनी पोनप्पा व तनीषा क्राष्टो तथा गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जौली से पदक तक पहुंचने के आशा है। एकल वर्ग में लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत व एचएस प्रणय भी लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन से दावेदारों में हैं। महिला एकल में मात्र पीवी सिंधू ही हैं जो पदक की दौड़ में है। लेकिन सिंधू का प्रदर्शन ढलान पर है। फिर भी पिछले ओलंपिक की कांस्य विजेता से लय में लौटने की उम्मीद की जा सकती है। मुक्केबाजी में महिला मुक्केबाज़ों ने पिछले साल हुई विश्व मुक्केबाजी में चार स्वर्ण पदक जीते। इससे विश्वास बना है कि निकहत जरीन, लवलीना, स्वीटी व नीतू में से कोई ज़रूर पदक जीतेगा। पुरुष मुक्केबाजों से उम्मीद कम ही हैं।

निशानेबाजी में 2004 ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा पहला रजत पदक जीतने, 2008 में अभिनव बिंद्रा के स्वर्ण पदक व 2012 में विजय कुमार के रजत व गगन नारंग के कांस्य पदक के बाद पदक का इंतजार है। लेकिन सरबजोत सिंह, एश्वर्य प्रताप सिंह, रिदम सांगवान, अमनप्रीत सिंह, वरुण तोमर, ईशा सिंह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारोत्तोलन में भी महिलाओं से उम्मीद है।

इनमें पिछली बार रजत जीतने वाली मीरा बाई चानू के समेत राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में नौ स्वर्ण के साथ 20 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में से भी कोई भी पदक जीतने का दमखम रखती हैं। कुश्ती में पिछले कुछ समय से देश में वातावरण सही नहीं रहा, उसका असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी पड़ रहा है। वे पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अंतिम पंचाल, सविता, प्रिया व दीपक पुनिया अच्छे प्रदर्शन से अन्य अनुभवी पहलवानों के साथ चौंकाते हुए पदक जीत सकते हैं।

हाकी में हमारा ओलंपिक में अतीत आठ स्वर्ण पदक, एक रजत व तोक्यो में मिले कांस्य सहित तीन कांस्य पदक के साथ गौरवमयी है। पुरुष हाकी टीम ने एशियाई चौंपियनशिप ट्राफी भी पिछले साल जीती है। ऐसे में विश्वास कर सकते हैं कि अपनी लय को बरकरार रखते हुए पदक देश की झोली में डालेंगे। हालांकि भारत में हुए विश्व कप में नौवें स्थान पर रहना पदक की आशा में खटक रहा है। इस साल पेरिस में हो रहा खेलों का यह महाकुंभ 1896 में अपने पहले आयोजन के बाद 128 साल का सफर पूरा कर रहा है। बात करें स्वतंत्र भारत की भागीदारी की तो 76 साल होने को है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक भारत किसी भी ओलंपिक में पदकों का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचा पाया है। फिर भी पूरे देश की निगाह तालिका में प्रथम 10 में आने से ज्यादा पहली बार 10 पदक जीतने पर होंगी।

विराट और कैसिगो की प्रतिद्वंद्विता देखकर बहुत आनंद आता है : एमफो रबादा

सेंचुरियन टेस्ट में सात विकेट चटकाकर दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कैगिसो रबादा की सफलता पर पिता डाक्टर एमफो रबादा का कहना है कि जब आप मैदान पर सर्वश्रेष्ठ देते हो तो आपको परिणाम भी मिलता है। कैगिसो का टेस्ट में स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है और उसने गेंदबाज के रूप में खुद को साबित किया है। प्रस्तुत है एमफो रबादा से विशेष बातचीत के अंशः-

सवालः- पहले टेस्ट मैच में अपने बेटे के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं?

जवाबः- मैं उसकी सफलता से बेहद प्रसन्न हूं। टेस्ट क्रिकेट में कैगिसो का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। उसने दिखाया कि वह करने में सक्षम है, लेकिन क्रिकेट के खेल में मैदान पर प्रदर्शन काफी अहमियत रखता है। पिछले रिकार्ड क्रिकेट में आपको किसी चीज की गारंटी नहीं देता है। आपको मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है और अगर आप सर्वश्रेष्ठ देते हो तो उसका परिणाम भी मिलता है।

सवालः- कैगिसो के स्कूल के दिनों में आप उनके ज्यादातर मैचों में उपस्थित रहते थे। एक डाक्टर होने के नाते आपके लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा? **जवाबः-** हां, ये सच है कि मैं उसके 90 प्रतिशत मैचों के दौरान उपस्थित रहता था। मुझे लगता है कि क्रिकेट के प्रति मेरा लगाव और कैगिसो की प्रतिभा को देखते हुए मैं ऐसा कर पाया। एक और कारण मेरा नौकरी नहीं करना रहा है। मैं खुद का क्लीनिक चलाता हूं, जिससे मैं इससे सामंजस्य बिठा पाया। मेरे लिए समय निकालना थोड़ा आसान रहा। अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मेरे लिए यह संभव नहीं होता।

सवालः- एक समय आया था जब कैगिसो को रग्बी या क्रिकेट में किसी एक खेल का चुनाव करना था। ऐसे में एक पिता के रूप मे आपने उन्हें क्रिकेट चुनने में मदद की?

जवाबः- हां, ये सही हैं। मैंने इस संबंध में स्कूल प्रिंसिपल और खेल निदेशक से मुलाकात की और कहा कि कैगिसो रग्बी नहीं खेलेगा। मैंने ये निर्णय उसके लिए लिया, लेकिन स्कूल इससे खुश नहीं था क्योंकि वह रग्बी में भी उतना ही अच्छा था। मेरा मानना है कि कभी कभी कोई निर्णय सही या गलत नहीं होता। शायद मैं भी गलत हो - सकता था, लेकिन कैगिसो ने क्रिकेट में जो - कुछ प्राप्त किया है, उसने दिखाया कि मैंने उस समय सही निर्णय लिया था।

सवालः- आपने हमेशा ही कहा है कि भारत आपकी दूसरी सबसे पसंदीदा टीम है। अगर दक्षिण अफ्रीका नहीं खेल रहा होता है तो आप चाहते हैं कि भारत जीते लेकिन पहले टेस्ट मैच में आपक भारत के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं?

जवाबः--पहली पारी में गेंद काफी मूव कर रही थी। अगर भारत पहले गेंदबाजी करता तो निश्चित रूप से उसके गेंदबाजों के कंडीशन से मदद मिलती। अगर भारत टास जीतकर गेंदबाजी चुनता तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय टीम भी उसी स्थिति में होती, जहां दक्षिण अफ्रीका थी। मेरा मानना है कि इस मैच में टास काफी अहम था। भारतीय टीम के प्रशंसक के तौर पर मैं टीम के प्रदर्शन से ज्यादा निराश नहीं - हूं। केएल राहुल ने शानदार पारी खेली, लेकिन जब वह बल्लेबाज़ी करने आए थे तो गेंद उतनी हरकत नहीं कर रही थी, जितनी दूसरे बल्लेबाजों के समय पर कर रही थी।

सवालः- आप संगीतज्ञ भी हैं तो कैगिसो के सफल करियर में संगीत का कितना योगदान रहा है?

जवाबः- जब भी आप तनाव में होते हो तो संगीत काफी मदद करता है। संगीत आपको शांति देता है और जब भी मैं और कैगिसो घर पर होते हैं तो संगीत पर काम करते हैं। धुन को लेकर काफी चर्चा करते हैं। क्रिकेट

स्वास्थ्य

दमा मरीज़ों का भीतर के प्रदूषण से बचना है ज़रूरी

दुनियाभर में हर साल लगभग चालीस लाख मौतें घर के अंदर के वायु प्रदूषण से होती हैं। खासकर भारत में, बीमारी के राष्ट्रीय बोझ का लगभग 4-6ः का ज़िम्मेदार घर के अंदर के वायु प्रदूषण को माना जाता है। घर के अंदर की खराब हवा यों तो सबको प्रभावित कर सकती है, पर दमा और सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) जैसे श्वसन रोगों में इसका अधिक बुरा प्रभाव होता है।

घर में वायु प्रदूषण और अस्थमा

अस्थमा के कारण मरीज के फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन आ जाती है। फेफड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में पहले से ही कमजोर श्वसन मार्ग में घर के अंदर की प्रदूषित हवा वायु मार्ग की सूजन को और बढ़ा देती है। बलगम ज्यादा निकलता है औरमार्ग संकरा होने से वायु की आवाजाही प्रभावित होती है। फेफड़ों की कार्यक्षमता घटती है। सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट जैसे लक्षण बढ़ते हैं। लंबे समय तक घर की खराब हवा में रहना अस्थमा के दौरों की आशंका बढ़ा सकता है। कई बार अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत हो सकती है।

भीतर की खराब हवा का कारण

खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल व बायोमास ईंधन का उपयोग (जैसे लकड़ी, फसल अपशिष्ट, कोयला और गोबर)।

तंबाकू या ई-सिगरेट पीने से निकलने वाला धुआं और सफाई करने वाले घरेलू उत्पादों के रसायनों का लंबे समय तक हवा में रहना।

सुगंधित मोमबत्तियां, धूप, मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां और एयर फ्रेशनर आदि।

जैविक प्रदूषक जैसे धूल कण, फफूंद, परागकण, रुका हुआ पानी, गद्दे व कालीन में पैदा होने वाले संक्रामक ।

दवाओं की अनदेखी न करें

अस्थमा ट्रिगर्स से निपटने और स्थिति का प्रबंधन करने में सांस के जरिए दवा देना उपचार का अभिन्न अंग है। दीर्घकालिक नियंत्रण वाली दवाएं जैसे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आदि वायुमार्ग में सूजन का इलाज करने और बीमारी को बढ़ने से रोकने में दी जाती हैं। आपातस्थितियों के लिए डॉक्टर द्वारा तुरंत राहत के लिए दिया गया इन्हेलर हमेशा रखें।

इन्हें अमल में लाएं

य घर में फफूंद, धूल कण व नमी अधिक है तो मास्क पहनें। हर समय दरवाजा बंद करके न रहें।

य फफूंद और नमी से बचने के लिए पानी की लीकेज को समय पर ठीक करें।

य कुकिंग उपकरणों की सर्विस कराते रहें। खिड़की, चिमनी खुली व साफ हों। रसोई में एग्जॉस्ट पंखा चलाएं।

य घर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष धूम्रपान से बचें। यवैक्यूम क्लीनर से साफ करें। गैस स्प्रे की जगह ठोस या तरल सफाई उत्पाद इस्तेमाल करें।

यबिस्तर, कालीन व पर्दे की सफाई पर ध्यान दें।

यएयर प्यूरी फायर भी लगा सकते हैं।

शेष – प्रथम पृष्ठ

की आस्था और स्वतंत्रता की भावना को समझने के लिए अपने पति के पास मौजूद कुरान का अध्ययन करना शुरू किया। उसका पति कोई रूढ़िवादी मुसलमान नहीं हैं। इसके अलावा वे मुसलमान नहीं हैं, बल्कि आम मुसलमान हैं, इसलिए वे कुछ इस तरह कहते हैंरू ष्मैं यह देखना चाहता था कि जब भी मुसलमानों (फिलिस्तीनियों) को मौत का सामना करना पड़े, तो वे अल्लाह की ओर मुड़ें। यही उनके प्रति मेरे भावनात्मक लगाव का कारण भी है। हालाँकि, इसी कारण मून ने भी शहादत का वचन पढ़ने के बाद मुसलमान बनने का फैसला किया। वह आगे कहती हैं कि पवित्र कुरान का अध्ययन करने और शहादत का वचन पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो भावना आई, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अस्तित्व प्रबुद्ध हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे वह आशीर्वाद मिल गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने जो किया वह मुझे मिल सकता है और मैं अपने आप में वापस आ गया। यह पवित्र कुरान में स्पष्ट है। यह हो चुका है कहा कि अल्लाह के सामने मर्द और औरतें बराबर हैं।

अन्य टिकटॉकर्स का कहना है कि कुरान महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करता है और सृष्टि के निर्माण के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या देता है और कुरान में बिग बैंग और अन्य सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। राइस का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि लोग विज्ञान को महत्व देते हैं और सभी वैज्ञानिक विज्ञान कुरान में निहित हैं। सिल्विया-चान मलिक, जो वर्तमान में रटगर्स विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन लोगों में से हैं जो इस्लाम की सच्चाई जानने के बाद मुसलमान बन गए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्लामोफोबिया के इतिहास पर भी शोध कर रही हैं। वह कहती हैं कि जब वह इस्लाम के करीब आईं तो उन्हें एहसास हुआ कि मीडिया इस्लाम को जिस नकारात्मक तरीके से चित्रित करता है वह वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है।

शेष – खाद्य तेलों के दामों में....

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से हम इस दिशा में सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि रिफंड के केस में देरी न हो, रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान किया जाए। वैट के पुराने और जीएसटी के केस में किसी व्यापारी से एक लाख रुपए लेने हैं, तो विभाग बैंक खाते में पड़े लाखों रुपए तक फ्रीज करा देता है। इससे ट्रेडर्स की गुडविल ख़राब होती है। जितनी देनदारी है, उसे रोकें और बाकी काम होने दें।

सवालः- लेकिन कई व्यापारी आज भी जीएसटी ले लेते हैं और सरकार को नहीं भरते, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए ?

जवाबः- सरकार ने ऐसे लोगों के लिए वेबसाइट बनाई है और पोर्टल पर बिल बनने के बाद सीधे चला जाता है। बामुश्किल एक प्रतिशत से कम लोग हैं। लेकिन सरकार को ऐसे डिफॉल्टर्स की सजा दूसरी पार्टी को न देकर, चोरी करने वाले को ही पकड़ना चाहिए।

सवालः- सदर, चांदनी चौक और आसपास के दुकानदारों को सीलिंग को लेकर आज भी भय का माहौल है?

जवाबः- कई साल से यह मुद्दा चल रहा है। मेयर, आयुक्त आदि से भी मिले अब स्थानीय अधिकारी कह रहे हैं कि लिखित में आदेश नहीं मिले हैं। कश्मीरी गेट, अमर कालोनी में दुकानों की सीलिंग की बात सुनाई दे रहे हैं। वैसे ही व्यापार मंदे की चपेट में है। एक व्यापारिक संस्थान सील होने से पांच से छह परिवार सड़क पर आ जाते हैं। ❑❑

शेष – बिलकिस केस में...

किसी ने बलात्कार और हत्या जैसे अपराध किए हों तो उस हाल में तो माफी बिलकुल ही मना होनी चाहिए।

राजनीति का डर : सुनने में आ रहा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिन दोषियों से सरेंडर करने को कहा है, वे अपने घरों पर नहीं हैं। हमें डर है कि वे कहीं महत्वपूर्ण लोगों के संरक्षण में तो नहीं हैं? मेरे मन में आशंका है कि अभी उन्हें जेल न जाना पड़े, इसलिए शायद दोषियों को घर से गायब दिखा दिया गया हो। अगर यह आशंका सही है तो फिर होगा यह कि वे सही चौनल से अप्लाई करेंगे। लेकिन राजनीति वहां क्या खेल खेलेगी, इसका पता नहीं है। आगे जैसा जो होगा, हम देखेंगे और उसी हिसाब से आगे के कदम तय होगे। ❑❑

शेष – बांग्लादेश : शिकंजे में मसीहा

को 30.48 अरब डॉलर का ऋण दिया था, जिनमें 97 फीसदी ज्यादा उधारकर्ता महिलाएं थीं।

राजनीतिक पार्टी का गठन

बढ़ती लोकप्रियता से उत्साहित मुहम्मद यूनुस ने सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार की मदद से वर्ष 2007 में बांग्लादेश की टकरावपूर्ण राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने के लिए अपनी 'सिटीजन पावर' पार्टी के गठन की घोषणा की। गरीबी उन्मूलन के लिए नोबेल यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक गरीबों को अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए छोटे और लंबी समयावधि के लिए कर्ज देता था, जिसके कारण लाखों लोग गरीबी के जाल से बाहर आए और यूनुस को गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। दुनिया भर के विकासशील देशों में मुहम्मद यूनुस की इस अवधारणा को अपनाया गया और छोटे व्यवसायियों को छोटे ऋण दिए जाने लगे, जिससे दुनिया में गरीबी में भारी कमी देखी गई। यही वजह थी कि वर्ष 2006 में मुहम्मद यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रसिद्धि ने यूनुस को न केवल बांग्लादेश में, बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया।

वैश्विक हस्तियों का समर्थन

जिन वैश्विक हस्तियों ने बांग्लादेश की सरकार को प्रोफेसर यूनुस के समर्थन में पत्र लिखा, उनमें सौ से ज्यादा नोबेल विजेताओं के अलावा बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, बान की मून सहित कई उद्योगपति, गायक व राजनेता शामिल है। इन लोगों ने पत्र में प्रोफेसर यूनुस पर लगातार हो रहे न्यायिक उत्पीड़न को रोकने की मांग की। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 83 वर्षीय मुहम्मद यूनुस पर अंतरराष्ट्रीय बयान जारी कराने के लिए 'भीख मांगने का आरोप लगाया और कहा कि वो प्रोफेसर यूनुस के ख़िलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का अध्ययन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का देश में स्वागत करती है।

कई किताबें लिखीं

प्रोफेसर यूनुस ने कई पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें बिल्डिंग सोशल बिजनेसः द न्यू काइंड ऑफ 'कैपिटलिज्म दैट्स सर्व ह्यूमैनिटीज मोस्ट प्रेसिंग नीड्स, बैंकर टू द पुअरः माइक्रो लेडिंग एंड द बैटल अगेंस्ट वर्ल्ड पॉवटी, ए वर्ल्ड ऑफ थ्री जोन्सः द न्यू इकनॉमिक्स ऑफ जीरो पॉवर्टी, जीरो अनइंप्लॉयमेंट एंड जीरो नेट, कार्बन इमिशन और क्रिएटिंग ए वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टीः सोशल बिजनेस एंड द फ्यूचर ऑफ, कैपिटलिज्म शामिल है।

आरोप और मुकदमे

जैसे ही शेख़ हसीना 2008 में सत्ता में लौटी, उनके ख़िलाफ न केवल सी से अधिक मामले दर्ज हुए बल्कि राज्य के नेतृत्व में इस्लामी संगठनों ने उन पर समलैंगिकता को बढ़ाया देने का भी आरोप लगायो। शेख़ हसीना ने उन्हें गरीयों को खून चूसने वालाश बताया। उन पर गरीबों से ज्यादा ब्याज वसूलने व विदेशों से हुई कमाई पर कर चोरी जैसे आरोप लगाए गए, जिनमें नोबेल पुरस्कार के साथ मिली नकद राशि और किताबों की रॉयल्टी भी शामिल थी। श्रम कानून, जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है, प्रोफेसर यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण टेलीकॉम के 18 पूर्व कर्मचारियों ने नौकरी के लाभी से दधिात रखने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ❑❑

शेष – तमिलनाडु: पोंगल के साथ...

है। एनडीए से अलग होने के बाद अन्नाद्रमुक किसी भी दल से कोई तालमेल नहीं बिठा पाई है। यह तय है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के विरोधी वोटों का विभाजन होगा और द्रमुक फायदे में रहेगी। फर्क सिर्फ यह पड़ा है कि अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन की संभावना बन गई है, पहले ये वोट द्रमुक की झोली में जा रहे थे, पर अब अन्नाद्रमुक की झोली में भी जाएंगे।

ऐसा नहीं है कि द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए भी सब कुछ ठीक चल रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री स्टालिन को सार्वजनिक रूप से दो बातों का खंडन करना पड़ा। पहली बात, उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बारे में और दूसरी बात, उनके बेटे उदयनिधि के उप-मुख्यमंत्री पद संभालने के बारे में। अफवाहें तब उड़ीं, जब स्टालिन का लोगों के बीच दिखना कम हुआ। यह भी अनुमान लगाया गया था कि स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि के साथ चिकित्सा कारणों से विदेश यात्रा कर सकते हैं।

तमिलों को विश्वास है कि थाई महीने का आगमन सभी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का भी मानना है कि तमिल नववर्ष एक नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। पोंगल या मकर संक्रांति के बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं और केंद्र में सत्तारूद भाजपा अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, मुकाबला तय है। ❑❑

शेष – विराट और कैसिगो की प्रतिद्वद्विता...

शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी थका देता है तो घर पर आकर कैगिसो संगीत सुनते हैं।.

सवालः- विराट कोहली और कैगिसो के बीच की प्रतिद्वंद्विता का आप कितना आनंद लेते हैं?

जवाबः- जब आप दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच प्रतिद्वंद्विता देखते हो तो आनंद आता ही है। जब विराट अच्छा स्ट्रोक लगा रहे थे तो मैं उनके लिए ताली बजा रहा था। जब कैगिसो विराट को गेंदबाजी कर रहे थे तो मैं बहुत उत्साहित था कि क्या होगा। क्या विराट उन्हें छक्का जड़ेंगे या विराट बोल्ड हो जाएंगे या कैच आउट होंगे। मेरे लि बहुत फिल्मी था। मुझे ये देखने में बह मज़ा आया।

सवालः- कैगिसो 500 अंतरराष्ट्रीय विकेट ले चुके है लेकिन हम टेस्ट में विकेट से एक गेंदबाज़ों को आंकते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ज्यान टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है। ऐसे में आप निकट भविष्य में एक टेस्ट गेंदबाज के रूप में अपने बेटे को कैसे देखते हैं?

जवाबः- -मेरा मानना है कि जब आप ज्यादा टे क्रिकेट नहीं खेलते हो और आपको जब टेस्ट खेलने का अवसर मिलता है तो अग उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास कर हो। स्ट्राइक रेट, औसत सुधारने के साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का प्रया करते हो। इसी उम्मीद में कि कभी भी कु बदल सकता है। आशा है कि आइसी) इस सिस्टम में बदलाव करेगी और दक्षि अफ्रीका को ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने मिलेगा। लेकिन अभी कम टेस्ट मैच रहे हैं तो उसी का लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। कैगिसो जल्द ही 400 विकेट भी लेंगे।

शेष – मंज़र पस-मंज़र

केवल एक सीट पर जीत मिली थी। ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी ब्लॉक 'इंडिया' में वह शामिल हो जाएंगी, पर लगता है, दोनों पक्षों की ओर से गठबंधन के ठोस प्रयास नहीं हुए और अपने-अपने फायदे की राजनीति ने अपना रंग दिखा दिया। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बसपा दूर ही रही है। भाजपा और बसपा की मिली-जुली सरकार तो उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, मगर सामाजिकता और विचारधारा, दोनों ही स्तर पर भाजपा और बसपा के बीच एक तरह की तल्खी शुरू से से रही है। पिछले दिनों बसपा की घोषणा से शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ होगा। वैसे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मायावती को साथ लेने के लिए ज्यादा प्रयास करने चाहिए था। यह भी ध्यान देने वालो बात है कि इंडिया ब्लॉक चूंकि फैसले लेने में काफी देरी कर रहा है, इसलिए बसपा जैसी अन्य संभावित सहयोगी पार्टियों के गठबंधन से बिदक जाने की आशंका बढ़ गई है। अब इंडिया की ओर से जितनी देरी होगी, उसे उतने ही ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। मायावती का गठबंधन में शामिल न होना, यास्तव में भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे को ही बल प्रदान करेगा। मायावती ने लगे हाथ यह भी इशारा कर दिया है कि गठबंधन उनके लिए कभी फायदेमंद नहीं रहा है और इससे उन्हें नुकसान हो ज्यादा होता है। वैसे, उनकी इस दलील पर सियासी बहस संभव है। देश में शायद ही ऐसा कोई दल है, जिसने सियासी गठबंधन से लाभ नहीं उठाया हो। देश में अनेक दलों की सत्ता तो गठबंधन से ही संभव हुई है। हालांकि, बसपा का यह संकेत मानीखेज़ है कि चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आगामी लोकसभा चुनाव में में बसपा अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी, जिससे अन्य सभी पार्टियों के मत प्रतिशत पर असर पड़ेगा। मायावती का अपना वोट बैंक है और अगर वह मजबूती से लड़ेंगी, तो बड़े गठबंधनों के समीकरण को भी प्रभावित कर सकती है। सोमवार को 69 साल की होने के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजनीति से संन्यास लेने की उनकी कोई योजना नहीं है। इससे उनके समर्थकों को निश्चित ही खुशी होगी और वे उम्मीद करेंगे कि मायावती पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे और ज्यादा में ज्यादा सीटें जीतकर भागी सत्ता गठबंधन में भागीदारी के लिए मजबूत दावा पेश करें। कुल मिलाकर तय है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : 21 Jan. 2024 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र मीम.सीन.जीम

•महंगाई की मार•ख़तरे पर पर्दा•बसपा अकेले रण में

महंगाई की मार

तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर क़ाबू पाना सरकार के लिए कठिन बना हुआ है। है पिछले महीने खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई 9.53 फीसद पर पहुंच गई। इसके पिछले महीने यह 8.70 फीसद पर थी, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 4.90 फीसद दर्ज की गई थी। यह महंगाई दर दालों, सब्जियों और मसालों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की वजह से दर्ज हुई है। हालांकि अनाज और खाद्य तेलों में मुद्रास्फीति कुछ कम हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था। इसीलिए उसने बैंक दरों में कोई बदलाव करने से परहेज़ किया। उसका मानना है कि सब्जियों और दालों की कीमतों में इस तरह के उतार-चढ़ाव आते रहेंगे और इसके लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है। रिजर्व बैंक की कोशिश रही है कि महंगाई को पांच फीसद से नीचे स्थिर रखा जाए। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मगर इस मामले में उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हालांकि इसके उलट, भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया में सबसे बेहतर यानी सात फीसद से ऊपर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

आर्थिक आंकड़ों के गणित में कुछ बातें बहुत सारे लोगों की समझ से परे या फिर विरोधाभासी लगती हैं। महंगाई के साथ औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी आए हैं, जिसमें तेईस में से सत्रह क्षेत्रों का प्रदर्शन निराशाजनक देखा गया है। औद्योगिक उत्पादन अपने पिछले आठ महीने के सबसे निचले स्तर पर यानी 2.4 फीसद दर्ज हुआ है। इसके पीछे उच्च आधार प्रभाव के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं और विनिर्माण गतिविधियों में शिथिलता को कारण माना जा रहा है। इसके बावजूद आर्थिक विकास दर में तेजी बताई जा रही है। जब औद्योगिक उत्पादन निराशाजनक हो, उपभोक्ता वैस्तुओं की खपत कम हो रही हो, व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा पाटना चुनौती बना हुआ हो, तब भी विकास दर ऊंची बनी रहे, तो इस पर हैरानी स्वाभाविक है। संतुलित विकास के लिए महंगाई दूर का नीचे रहना, औद्योगिक उत्पादन का संतोषजनक दर से वृद्धि करना, रोजगार के नए अवसर सृजित होते रहना और बाजार में पूंजी का प्रवाह संतुलित रहना बहुत जरूरी होता है। महंगाई, खासकर खाने-पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी, आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर डालती है। कोरोनाकाल के बाद कारोबारी गतिविधियां सामान्य ढंग से चल तो पड़ी, मगर रोजगार और आय के स्तर पर बहुत सुधार नहीं देखा गया। लोगों की कमाई बढ़ नहीं पा रही है। जिन लोगों के रोजगार छिन गए, उनमें से बहुत सारे आज भी खाली हाथ बैठे हैं। इस तरह सबसे अधिक बुरा प्रभाव लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ा है। इसकी वजह से कुछ त्योहारी मौसमों को छोड़ दें, तो उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में रौनक अभी तक स्वाभाविक ढंग से नहीं लौटी है। मगर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कृषि उत्पादों के भंडारण, बाजारों तक उनकी सुगम पहुंच और विक्रय नीतियों में असंतुलन की वजह से अधिक देखी जाती है। यह मौसम आमतौर पर सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिहाज से अच्छा माना जाता है। मौसम भी आमतौर पर अनुकूल ही रहा है। फिर भी सब्जियों की कीमतों में सत्ताईस फीसद से अधिक बढ़ोतरी देखी गई, तो खेतों से उपभोक्ता तक उनके पहुंचने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने पुर विचार की जरूरत है। महंगाई की मार से बचाने के लिए लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने के उपाय जुटाना इस वक्त की बड़ी चुनौती है।

ख़तरे पर पर्दा

किसी संक्रामक या जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए सबसे जरूरी है उसके प्रसार और असर पर नजर रखना, ताकि उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जा सके और उसी मुताबिक उस पर क़ाबू पाने के उपाय जुटाए जाएं। हैरानी की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक और आम लोगों के लिए डेंगू का जोखिम बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर संबंधित महकमे इसकी हकीकत को छिपाने की कोशिश में लगे हैं। दिल्ली में हर साल डेंगू के बढ़ते जोखिम और इसकी वजह से लोगों की मौत की खबरें चिंता का कारण बनती रही हैं। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक भी बीते वर्ष उन्नीस लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो गई। मगर हैरानी की बात है कि इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने और मरने वालों के वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर दिल्ली नगर निगम ने एक तरह की चुप्पी ओढ़ ली थी। जबकि यह रवैया किसी भी बीमारी के बेलगाम हो जाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है।

यह बेवजह नहीं है कि अब दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर समय-समय पर मच्छरजनित बीमारियों या खासकर डेंगू के दंश से पीड़ित और मरने वालों को लेकर दर्ज आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए और कई महीनों तक इससे संबंधित आंकड़ों को क्यों छिपाया गया! खबरों के अनुसार, पिछले वर्ष अगस्त के बाद से दिल्ली नगर निगम ने अपनी हर सप्ताह जारी होने वाली मच्छरजनित रोगों के आंकड़ों वाली रपट जारी नहीं की है, जबकि 2023 में डेंगू के करीब सवा नौ हजार मामले प्रकाश में आए और इससे कुल उन्नीस लोगों की जान चली गई। मच्छरजनित बीमारियों या फिर अन्य संक्रामक रोगों के फैलाव तथा असर पर नजर रखना और उससे संबंधित रपट जारी करना नगर निगम का दायित्व है। इससे बीमारियों की रोकथाम में मदद ही मिलती है। मगर इस मामले में हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और ऐसे आरोप सही हैं, तो क्या यह आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं है!

यह एक सामान्य तथ्य है कि अगर किसी बीमारी की प्रकृति को शुरुआती दौर में ही ठीक से समझने की कोशिश नहीं की जाती, तो इसे पांव पसारने का मौका मिलता है। इस बात की आशंका भी खड़ी हो सकती है कि वह बीमारी गंभीर शक्ल लेकर बेलगाम हो जाए। कोरोना के महामारी में तब्दील हो जाने और उसके नतीजों के ब्योरे आज भी लोगों को दहला देने के लिए काफी हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान उसकी चपेट में आने वाले मरीजों से संबंधित सभी आंकड़ों पर नजर रखी गई थी और उससे इसके असर का सटीक अध्ययन करने में काफी मदद मिली। आज कोरोना का असर नगण्य है, तो इसमें इससे जुड़े सभी पहलुओं को देख-समझ कर उसी मुताबिक इससे निपटने के उपाय करने की सबसे बड़ी भूमिका रही। अब अगर डेंगू के मामले में दिल्ली नगर निगम पर सच्चाई छिपाने के आरोप लग रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यह कौन और क्यों कर रहा है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिल्ली में एक समय डेंगू के देश से भयावह हालात पैदा हो चुके हैं। अगर इसकी वास्तविक तस्वीर पर नजर नहीं रखी गई तो कभी भी इसके गंभीर खतरे झेलने की स्थिति खड़ी हो सकती है।

बसपा अकेले रण में

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने उचित ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इस घोषणा का सर्वाधिक असर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के परिणामों पर पड़ेगा। चूंकि मायावती अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, इसलिए भी उनका अलग चुनाव लड़ना जमीनी राजनीति को प्रभावित करेगा। पिछले आम चुनाव में बसपा राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी थी और उसे 10 सीटें मिली थीं। हालांकि, यह बात भी ग़ौर करने की है कि पिछला लोकसभा चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। गठबंधन से ज़्यादा लाभ बसपा को ही हुआ था, पर इस बार इन दोनों दलों के बीच समन्वय की सूरत नहीं बन पा रही है। वैसे, उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा अलग होकर लड़ी थी और उसे

बाक़ी पेज 11 पर

इतनी जल्दी सुलझने के पीछे रूस का हाथ?

1979 की क्रांति ने ईरान को एक शिया मुस्लिम धार्मिक शासन प्रणाली पर आधारित (धर्म तंत्र) देश बना दिया जो अब पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ जाने के कारण स्वयं को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ईरान फारस की खाड़ी में खुद को सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में देखता है जहां उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी अमरीका का सहयोगी और मुख्य सुन्नी बहुसंख्यक मुस्लिम देश सऊदी अरब है। ईरान के शासक अमरीका और इसराईल को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। कई दशकों से ईरान अपने शत्रुओं को कमज़ोर करने की कोशिश में लगा है जिसके लिए वह पश्चिमी एशिया में समान विचारधारा वाले देशों की सेना को मजबूत बनाने में मदद करता है।

ईरान किसी भी गुट के लिए हथियार नहीं उठाता परंतु उन्हें आर्थिक सहायता देता है। इसी श्रृंखला में वह लेबनान, ईराक और यमन में शिया समूहों और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में इसराईल विरोधी सुन्नी हमास और हिजबुला को सहायता देता है। उसने दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियारों की मदद और ट्रेनिंग तथा भरपूर आर्थिक सहायता दी है। इसी कारण आज हर जगह इसका कोई न कोई शलिकश निकल आता है।

अभी तक ईरान की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती थी और हाल ही में ईरान द्वारा पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद इन दोनों द्वारा झटपट अपना विवाद सुलझा लेने पर सब हैरान हैं। इसका कारण यह है कि ईरान सरकार को वर्ष 2024 में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि सरकार के विरुद्ध पैदा होने वाले अंसतोष से देशवासियों का ध्यान बाहर के शत्रुओं की ओर भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया जो एक मित्र देश है। हालांकि अब ईरान और पाकिस्तान एक-दूसरे पर बलूचिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाते रहे हैं जबकि बलूचिस्तान 3 देशों ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में बंटा हुआ है जबकि 1947 में वह भारत में विलय चाहता था। बलोच आतंकवादी आधे पाकिस्तान और आधे ईरान में हैं तथा इनको प्रशिक्षित करने के ईरान और पाकिस्तान दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

चर्चा है कि ईरान का पाकिस्तान के साथ यह 'फ्रंट' क्या रूस के कारण बना है जिसके ईरान के साथ अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ईरान और पाकिस्तान में इतनी जल्दी सुलह हो गई है? या फिर चीन भी इसमें शामिल है क्योंकि वह दोनों से अच्छे रिश्ते रखता है और चीन नहीं चाहता है कि दुनिया का ध्यान इसराईल और फिलिस्तान से हटे और देखना है कि यदि लाल सागर के क्षेत्र में टकराव बढ़ता है तो क्या रूस भी इसमें ईरान के पक्ष में कूदेगा? क्या यह विवाद और भड़केगा या सुलझ जाएगा ? इसका जवाब तो समय ही देगा!

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

1. मनीआर्डर द्वारा
2. ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SHANTI MISSION
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन :- 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173